▪ RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 333 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » शुक्रवार » 03-07-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 अखिलेश ने सासंद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की निंदा की

6 'इंडिया' नहीं, 'भारत': राष्ट्रीय अस्मिता का पुनर्जागरण

7 जो मेरी पोस्ट पसंद करते हैं, वही सबसे ज्यादा खुश, समझदार और खूबसूरत हैं : काजोल

फर्स्ट टेक

'सॉक स्ट्रीट' ने एमएमए एथलीट संग्राम को बनाया ब्रांड दूत

नई दिल्ली/भाषा। 'सॉक स्ट्रीट' ने एमएमए (मिश्रित मार्शल आर्ट) एथलीट संग्राम सिंह के साथ मिलकर अपना 'कम्प्रेशन परफॉर्मेंस गियर' लांच किया है। मोजे बनाने वाली कंपनी 'सॉक स्ट्रीट' ने 'दौड़ने और स्ट्रेंथ' ट्रेनिंग से लेकर फिटनेस जैसी गतिविधियों के लिए इस गियर को डिजाइन किया गया है। 'फिट इंडिया' आइकन संग्राम सिंह ने कहा, हर एथलीट का सफर अनुशासन, निरंतरता और लगातार बेहतर करने की इच्छा पर टिका होता है। इन सभी चीजों ने कुश्ती और एमएमए में मेरा मार्गदर्शन किया है। सॉक स्ट्रीट का यही फलसफा मुझे व्यक्तिगत लगा।

जया बच्चन ने ममता बनर्जी से मुलाकात की

कोलकाता/भाषा। विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद विपक्ष के नए सिरे से एकजुट होने की चर्चा के बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की। बच्चन दोपहर में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन के साथ बनर्जी के आवास पर पहुंचीं। बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकी है। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने कोलकाता दौरे के दौरान चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को ज़िम्मेदार ठहराया था और कहा था कि लोग ममता को नहीं चाहते थे।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें तीन करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत से और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया था। एजेंसी ने यह कहते हुए गहलावत की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया कि उसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, पैसे के स्रोत और उससे फायदा उठाने वालों की पहचान करनी है। एजेंसी ने मामले के दूसरे सह-आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की आवश्यकता का हवाला दिया। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की अर्जी खारिज की जाती है।

बेंगलूरु में पत्थर की खदान में विशाल चट्टान गिरने से सात श्रमिकों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु शहरी जिले में बृहस्पतिवार को पत्थर की एक खदान में विशाल चट्टान गिरने से सात श्रमिकों की मौत हो गई जिनमें पांच मध्यप्रदेश के थे। यह जा

नकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। अधिकारी ने इस घटना के लिए ''लापरवाही'' को जिम्मेदार ठहराया। शुरू में पुलिस सूत्रों ने कहा था कि हताहत होने वाले लोगों में ज्यादातर बिहार के हैं, लेकिन बाद में साफ़ किया गया कि वे मध्यप्रदेश के थे। यशवंतपुर के विधायक एस.टी. सोमशेखर ने दावा किया था कि अस्पताल में एक घायल श्रमिक के दम तोड़ देने के साथ ही मृतकों की संख्या आठ हो गई। हालांकि, मध्य क्षेत्र के उपमहानिरीक्षक एस. गिरीश ने स्पष्ट किया कि बेंगलूरु शहरी ज़िले में बेंगलूरु दक्षिणी ज़िले की सीमा से सटे मडापट्टना में हुई इस घटना में सात लोगों की मौत हुई, पांच घायल हुए, जबकि चार अन्य को कोई चोट नहीं पहुंची। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें पांच मध्यप्रदेश के, एक छत्तीसगढ़ का और एक कर्नाटक के यादगीर का था।

गिरीश ने यहां पत्रकारों से कहा, यहां दो क्रशर हैं – एक ऊपर और दूसरा नीचे। दोनों जगहों पर काम हो रहा था। वहां करीब 16 मजदूर काम कर रहे थे। ऊपर एक ड्रिलिंग मशीन लगी हुई थी। ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर खिसककर नीचे काम कर रहे लोगों पर गिर गया। सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पांचों घायल खतरे से बाहर हैं। अधिकारी ने कहा, यह साफ़ है कि लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से सात लोगों की जान चली गई। खान और भूगर्भ विज्ञान विभाग के अधिकारी रंगप्पा ने बताया कि खदान मालिक मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गया है। रंगप्पा ने पत्रकारों से कहा, मैंने खदान मालिक से बात की है ताकि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायल व्यक्तियों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवज़ा मिल सके। वह इसके लिए सहमत हो गया है। मज़दूरों की मौत पर दुख जताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा, ''हम पूरे राज्य में पत्थर निकालने के काम के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो।'' उन्होंने कहा कि वह इस बात की जांच कराएंगे कि राज्य में पत्थर निकालने का काम नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है, जो इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।

लोकप्रिय और चर्चित 'यूजरनेम' आरक्षित करने के दावे गलत : व्हाट्सऐप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संदेश ऐप व्हाट्सऐप ने चर्चित सार्वजनिक हस्तियों के नाम से जुड़े 'यूजरनेम' केवल उनके वैध खाताधारकों के लिए ही आरक्षित होने की जानकारी दी है। साथ ही लोकप्रिय या चर्चित 'यूजरनेम' पहले से आरक्षित किए जाने के दावों को गलत करार दिया है। मेटा के स्वामित्व वाले संदेश मंच ने अपने विवादित 'यूजरनेम' सुविधा से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) में यह स्पष्टीकरण दिया। यह 'फीचर' किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने (इम्पर्सनेशन) और धोखाधड़ी की आशंकाओं को लेकर विवादों में है।

व्हाट्सऐप ने कहा, एक और बात ध्यान रखने की है... कुछ लोग यह गलत दावा कर रहे हैं कि लोकप्रिय या चर्चित 'यूजरनेम' पहले से आरक्षित किए जा रहे हैं। यह सही नहीं है। चर्चित सार्वजनिक हस्तियों के नाम वाले 'यूजरनेम' केवल उनके वैध खाता धारक ही आरक्षित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को व्हाट्सऐप पर प्रस्तावित इस फीचर' को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका जताई कि इससे 'ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर अपराध और पहचान की नकल करने के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार ने कहा है कि इन मुद्दों पर उसकी संतुष्टि होने और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस सेवा को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

भारत व्हाट्सऐप के लिए प्रमुख बाजार है और देश में इसके 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर हाल ही में कई प्रमुख हस्तियों ने शिकायत की थी कि यूजरनेम' आरक्षण की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान उनके नाम के अधिकतर विकल्प पहले ही आरक्षित हो चुके हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 'एक्स' पर लिखा कि उनके नाम के लगभग सभी विकल्पों के साथ-साथ उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े नाम भी पहले ही आरक्षित दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मोबीक्विक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बिपिन प्रीत सिंह ने भी पाया कि उनके नाम से मिलते-जुलते कई 'यूजरनेम' शुरुआती आरक्षण चरण में पहले ही लिए जा चुके हैं।

भारत, जापान ने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की

मोदी ने भारत-जापान संबंधों की मजबूती और उनके महत्व पर भी प्रकाश डाला। कुछ दिन पहले ही जी7 शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक संसाधन है। प्रधानमंत्री ने कहा, और मुझे गर्व है कि भारत-जापान साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और जापान ने बृहस्पतिवार को आर्थिक साझेदारी ढांचा और सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रक्षा समझौते समेत कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष सनाए तकाइची के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद इन कदमों की घोषणा की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें आर्थिक सुरक्षा पर एक घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त वक्तव्य और ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में सहयोग को मजबूत करने के वास्ते एक समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा, ''भारत और जापान की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकी तक, हमारी सोच और कार्यप्रणाली में भी समानता है।''

उन्होंने कहा, ''हमारे संबंधों की नींव अटूट पारस्परिक भरोसे पर टिकी है।'' उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आर्थिक सुरक्षा के लिए एक संयुक्त खाका तैयार किया है। मोदी ने कहा, ''इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति शृंखला को अधिक सुदृढ़ और लचीला बनाएंगे।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा, ''भारत-जापान बायोगैस पहल के माध्यम से हम भारत में एक हजार बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करेंगे। इससे भारत के गांवों में समृद्धि आएगी तथा ग्रामीण आजीविका को और मजबूती मिलेगी।''

मोदी और तकाइची की मौजूदगी में आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े प्रमुख समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और जापान ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक सूची पर भी सहमति जताई। मोदी ने भारत-जापान संबंधों की मजबूती और उनके महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''कुछ दिन पहले ही जी7 शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक संसाधन है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''और मुझे गर्व है कि भारत-जापान साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी है।'' मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नई गति और मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ''रक्षा क्षेत्र में, हमने भारत और जापान के बीच पहले संयुक्त विकास परियोजना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।'' जापान की प्रधानमंत्री तीन दिवसीय भारत यात्रा पर हैं।

रूस का कीव पर ड्रोन हमला, 18 लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कीव/एपी। रूस ने बृहस्पतिवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक अन्य घायल हो गए। हमलों के दौरान कई घंटों तक राजधानी में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। रूस ने इस हमले को यूक्रेन की ओर से मॉस्को के तेल प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों का प्रतिशोध बताया है। यूक्रेन के इन हमलों से रूस में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ा है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों तथा ड्रोन से किए गए इस हमले में राजधानी के कई हिस्सों में आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों की ओर से हमले को लेकर पहली बार सतर्क किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने सबवे स्टेशनों में शरण ली। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हमला यूक्रेन की ओर से रूस के नागरिक बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया।

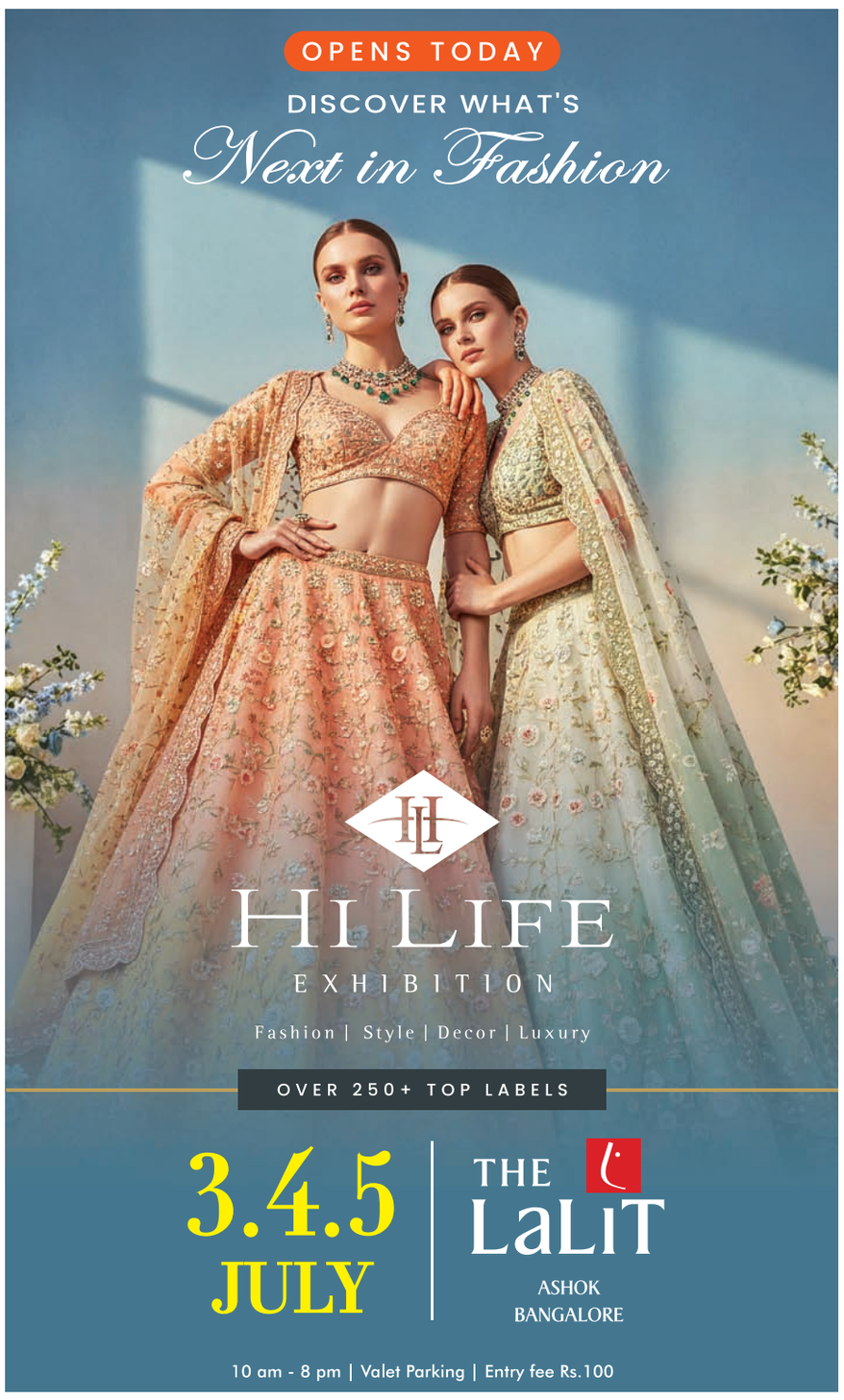

03-07-2026 सूर्यास्त 6:50 बजे | 04-07-2026 सूर्योदय 6:00 बजे

BSE	NSE
77,502.12 (+ 579.48)	24,175.70 (+169.86)

सोना	चांदी
14,805 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	238,528 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

सब कुछ बाँटो

प्रतिबंधित एयरस्पेस हुए,
अवरोध बने सीमाओं पे।
नदियों का जल भी बाँट लिया,
झगड़ा वृक्षों की छाँहों पे।
सागर के पानी पर लकीर,
भूगर्भ युद्ध के दावों पे।
बादल खुशबू अरदास करे,
अंकुश ना लगे हवाओं पे।।

रक्तदान के बदले ओंकारेश्वर में 'वीआईपी दर्शन', शिवभक्त हर हफ्ते दे रहे 200 यूनिट तक खून

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

खंडवा/भाषा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में भगवान शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रशासन की अनूठी पहल के तहत रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को 'वीआईपी दर्शन' का पास दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था से प्रशासन को हर सप्ताह 150 से 200 यूनिट खून मिल रहा है, जबकि शिवभक्त लंबी कतारों से बचकर अपने परिवार के साथ शीघ्र दर्शन कर पा रहे हैं। जिलाधिकारी ऋषव गुप्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''हमने देखा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए खून की मांग बढ़ती जा रही है। रक्तदान शिविरों में मिलने वाला खून खासकर आपातकालीन वॉर्ड में भर्ती मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं होता।''

गुप्ता ने कहा, ''इन हालात के मद्देनजर हमने रक्तदान को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में वीआईपी दर्शन से जोड़ा ताकि श्रद्धालुओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा सके।'' जिलाधिकारी ने बताया, श्रद्धालुओं ने इस पहल को हमारी उम्मीद से कहीं अधिक समर्थन दिया। हम देख रहे हैं कि हमें ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं से प्रत्येक सप्ताह 150 से 200 यूनिट खून मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण लोगों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आमतौर पर तीन से चार घंटे तक कतार में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन रक्तदान करके वे 'वीआईपी पास' हासिल कर सकते हैं और अपने पूरे परिवार समेत तुरंत दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को इसके प्रमाण पत्र के साथ ही मंदिर का प्रसाद और भगवान ओंकारेश्वर की तस्वीर भेंट के तौर पर दी जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. ओपी जुगतावत ने बताया कि इस पहल से जहां स्थानीय ब्लड बैंक में खून की किल्लत दूर हो गई है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं का रक्त आस-पास के जिलों में भर्ती रोगियों की जान बचाने में भी मददगार साबित हो रहा है।

आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री नायडू और केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीबी जी-राम-जी योजना की शुरुआत की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुपति/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को तिरुपति जिले में वीबी जी राम जी योजना की औपचारिक रुप से शुरुआत की।

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 बुधवार से पूरे देश में लागू हो गया। केंद्र सरकार के अनुसार, इस कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार का वैधानिक अधिकार मिलेगा।

एक सरकारी बयान में कहा गया है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेलवे कोडूरु विधानसभा क्षेत्र के ओबुलावरिपल्ले मंडल के मुक्कावरिपल्ले गांव में वीबी जी-राम-जी कार्यक्रम की शुरुआत की।'' इस अवसर पर नायडू, चौहान एवं पवन कल्याण ने लाभार्थियों को वीबी जी-राम-जी कार्ड वितरित किए।

हिमंत ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

हवाई अड्डा परियोजनाओं और बाढ़ पुनर्वास पर की चर्चा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू से मुलाकात की और राज्य में प्रस्तावित छह नए हवाई अड्डों की परियोजना पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि सरकार न केवल संपर्क सुविधा बेहतर बना रही है, बल्कि लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने का भी लक्ष्य रख रही है। शर्मा ने इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू से भी अलग से मुलाकात की और राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, अभी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू जी के साथ एक बहुत ही सार्थक बैठक हुई। वह असम को एक प्रमुख विमानन और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने के हमारे दृष्टिकोण को पूरे उत्साह के साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने असम के सिलचर, मानस, उमरांगसो, माजुली, दिफू और चराइदेव में प्रस्तावित छह नए हवाई अड्डों और हाफलोंग में एक हेलीपोर्ट की स्थिति पर चर्चा की। शर्मा ने कहा, सिलचर के नए हवाई अड्डे के लिए हमने अधिकतर शुरुआती काम पूरे कर लिए हैं और मैंने मंत्रालय से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। अन्य प्रस्तावित हवाई अड्डों के लिए, हम व्यावहारिकता अध्ययन के कार्य में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक उन्होंने नायडू के साथ बैठक के दौरान रूपसी हवाई अड्डे के विस्तार कार्य की भी समीक्षा की। शर्मा ने रीजीजू के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया कि उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए असम के हालिया दौरे के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, ''आज दिल्ली में मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू के साथ एक सार्थक बैठक हुई। मैंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हाल ही में असम का दौरा करने पर उनका आभार व्यक्त किया। हमारी बैठक के दौरान उन्होंने कुछ बहुत ही मूल्यवान विचार भी साझा किये।'' शर्मा ने कहा कि बातचीत के केंद्र में राज्य में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के प्रयासों को मजबूत करना रहा।

मुंबई में भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। मुंबई में लगातार भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरकर बह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

चांदीवली इलाके में जलभराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का पता नहीं चल सका और वह उसमें गिरकर बह गया। अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दल और नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम ने संयुक्त रूप से खोज एवं बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद बृहस्पतिवार को व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया।

उपमहापौर संजय घाडी ने कहा कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने ठेकेदार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे गैर-इरादतन हत्या का मामला बताया।

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भोपाल/भाषा। निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी, जिसके तहत 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि परिणाम तीन अगस्त को आएंगे।

पिछले चुनाव में दतिया से जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

भारती को आर्थिक अनियमितता से जुड़े एक मामले में अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट खाली घोषित कर दी थी।

कांग्रेस नेता ने इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी है। हालांकि, उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर उपचुनाव कराया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार, छह जुलाई को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 13 जुलाई तक चलेगी। आयोग के मुताबिक, 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 16 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। उसने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया चार अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

ओडिशा के कई सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता और कैडर पुनर्गठन सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले लगभग 8,000 चिकित्सकों ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला मुख्यालय अस्पतालों और उपखंडों व ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में काम बंद आंदोलन शुरू किया था। एक अधिकारी ने बताया हालांकि, मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक काली पट्टी पहनकर मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं जारी रखी हैं।

प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों की प्रमुख मांगों में कैडर पुनर्गठन, केबीके (कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट) एग्जिट पॉलिसी, स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता, बीमा, प्रोत्साहन तथा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अनुरूप डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन' (डीएसीपी) लाभ शामिल हैं। कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट (केबीके) क्षेत्र में चिकित्सकों के लिए तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा समझौता है हालांकि एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी उनका स्थानांतरण नहीं किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के बाद 46 सड़कें बंद, 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

शिमला/भाषा। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने से जनजीवन बाधित हुआ है तथा 46 सड़कें बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। शिमला मौसम केंद्र ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए तीन जुलाई को छोड़कर दो से पांच जुलाई तक छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, कुल्लू में 18, मंडी में 15, सिरमौर में नौ और लाहौल-स्पीति व ऊना ज़िलों में दो-दो सड़कें बंद कर दी गईं। एसईओसी ने बताया कि भारी बारिश की वजह से बिजली के 181 ट्रांसफ़ॉर्मर और जलापूर्ति की छह योजनाएं भी प्रभावित हुईं। कांगड़ा, जुब्बरहट्टी और भुंतर में भी आंधी-तूफ़ान आया और बिजली कड़कने की घटनाएं हुईं। शिमला के ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉनसून के दौरान आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम तैनात की है। इस बीच, एनएचएआई ने मॉनसून के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुचारू और बिना रुकावट के यातायात सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं।

शक्तिशाली माइक्रोफोन से रिकॉर्ड से बाहर की बातें भी हो सकती हैं 'रिकॉर्ड': केरल विधानसभा अध्यक्ष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पत्तनमथिट्टा/भाषा। केरल विधानसभा अध्यक्ष तिरुवनचूर राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि विधानसभा में लगे माइक्रोफोन बहुत शक्तिशाली हैं और कभी-कभी ऐसी बातें भी उनमें रिकॉर्ड हो सकती हैं जो सदन के रिकॉर्ड से बाहर होती है लेकिन केवल उन्हीं बयानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

राधाकृष्णन ने पिछले सप्ताह विधानसभा में किए गए एक अनुरोध पर मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के जवाब के बाद माइक चालू रहने के दौरान की गई मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी संबंधी विवाद पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह कहा। कुट्टनाड से विधायक रेजी चेरियन (केरल कांग्रेस-जोसेफ) ने एक वार्षिक आयोजन के लिए कुट्टनाड में स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। चेरियन की पार्टी सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की घटक है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा था कि ''सरकार इस अनुरोध पर विचार करेगी लेकिन अपनी सीट पर बैठने के कुछ ही क्षण बाद सतीशन को खुले माइक पर कथित तौर पर यह कहते सुना गया, किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।'' यह टिप्पणी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई और एलडीएफ विधायकों द्वारा सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हमारे पास बहुत शक्तिशाली माइक्रोफोन हैं इसलिए कुछ बातें सुनाई दे सकती हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज बातों पर ही विचार किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारे को गिराए जाने की निंदा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

होशियारपुर/भाषा। पंजाब के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय सांपला ने पाकिस्तान में करीब 125 वर्ष पुराने एक गुरुद्वारे को कथित तौर पर ढहाए जाने की घटना की बृहस्पतिवार को निंदा करते हुए इसे सिख समुदाय की आस्था और विरासत पर हमला बताया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फारूकाबाद स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को हाल ही में एक स्थानीय कारोबारी ने आवश्यक अनुमति के बिना कथित तौर पर ढहा दिया। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक सिख समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। सांपला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों पर हमले, उपासना स्थलों पर अतिक्रमण और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव की घटनाएं बार-बार सामने आती रही हैं, जिससे सिखों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। उन्होंने हिंदू और सिख समुदाय की महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों के कथित जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है।

सांपला ने कहा, ''यदि ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा नहीं की जा सकती, तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।'' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार को केवल आश्वासन देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों का विश्वास बहाल हो सके। भाजपा नेता ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ''दृढ़ कूटनीतिक प्रतिक्रिया'' का स्वागत करते हुए पाकिस्तान से कथित ध्वस्तीकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को उसके मूल ऐतिहासिक स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उपासना स्थलों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा केवल किसी एक देश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़ा विषय है।

हनीमून हत्याकांड : सोनम को जमानत देने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची मेघालय सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। मेघालय सरकार ने 2025 में राज्य में अपने पति की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दिए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की मुख्य आरोपी को जमानत देकर गलती की है। उन्होंने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया। मेहता ने कहा कि सोनम को इस आधार पर जमानत दी गई कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तार किए जाने के आधारों की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का मामला एक ऐसे प्रावधान से जुड़ा है, जिसका उल्लेख टाइपिंग की गलती की वजह से गलत तरीके से हो गया था। मेहता ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी के फरार होने की आशंका है। पीठ ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। मेघालय उच्च न्यायालय ने सोनम रघुवंशी को जमानत देने के एक अधीनस्थ अदालत के आदेश को 29 जून को बरकरार रखा था। हनीमून के लिए मेघालय आया यह नवविवाहित दंपति पिछले वर्ष 23 मई को सोहरा इलाके में लापता हो गया था। इसके बाद राजा रघुवंशी का शव दो जून 2025 को एक गहरी खाई में मिला था।

विजयन ने मंजूरी के बिना बंदरगाह संबंधी हिस्सेदारी हस्तांतरण को लेकर अदाणी समूह पर निशाना साधा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को सवाल उठाया कि राज्य सरकार की अनिवार्य पूर्व अनुमति के बिना अदाणी समूह ने विड़िण्गम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का समझौता करने का ''साहस'' कैसे किया।

विजयन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बंदरगाह को लेकर कंपनी और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, राज्य प्रशासन की पूर्व अनुमति के अधीन ही अदाणी विड़िण्गम पोर्ट प्राइवेट लि. (एवीपीपीएल) में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की अनुमति है। हालांकि, विड़िण्गम बंदरगाह की 'कंसेशन-होल्डर' कंपनी एवीपीपीएल ने राज्य सरकार की ऐसी पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही 13,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अपनी 49% हिस्सेदारी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग व लॉजिस्टिक्स कंपनी, स्विट्जरलैंड की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) को हस्तांतरित करने का समझौता कर लिया है। माकपा के नेता ने कहा, ''वे ऐसा करने का साहस कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बंदरगाह विभाग का भी प्रभार है।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ''हिस्सेदारी हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करना गैर कानूनी है और यह सरकार के साथ हुए समझौते का उल्लंघन है। अदाणी समूह के इस कदम के मद्देनजर सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, इस पर भी मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए।'' मंगलवार को अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन' (एपीएसईजेड) ने घोषणा की थी कि एमएससी, एवीपीपीएल में 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर में 49% हिस्सेदारी खरीदेगी। विजयन ने कहा कि भले ही कुछ लोग इसे राज्य में बड़े विदेशी निवेश के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में यह अदाणी समूह की मुनाफ़ा कमाने की कोशिश है और इससे एमएससी का बंदरगाह पर एकाधिकार हो सकता है।

ईपीएफओ की नई योजनाओं में डिजिटल अनुपालन एवं दावों के समयबद्ध निपटान पर रहेगा जोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संचालित नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डिजिटल अनुपालन और भविष्य निधि (पीएफ) निकासी तथा पेंशन निर्धारण जैसे दावों के समयबद्ध निपटान पर विशेष जोर रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026, कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

मंत्रालय ने नई योजनाओं में ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि निकासी, पेंशन तथा समूह बीमा संबंधी दावों का 20 दिन के भीतर निपटान नहीं करने पर 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक दंडात्मक ब्याज का सख्त प्रावधान किया है। नई योजनाओं में कहा गया, यदि आयुक्त बिना उचित कारण के सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद किसी दावे का 20 दिन के भीतर निपटान नहीं करते हैं, तो उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए आयुक्त जिम्मेदार होंगे। लाभ राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है, जिसे आयुक्त के वेतन से काटा जाएगा। नई योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976 का स्थान लेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पहले की योजनाओं में भी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दावों के निपटान में देरी होने पर दंडात्मक ब्याज का प्रावधान था। पहले संबंधित अधिकारियों को भविष्य निधि जमा पर घोषित ब्याज दर के बराबर राशि देनी होती थी, जबकि अब इसे 12 प्रतिशत वार्षिक की निश्चित दर पर तय कर दिया गया है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान के नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पहले की तरह मूल वेतन का 12-12% सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान देते रहेंगे। नियोक्ता के 12% अंशदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाएगा जबकि केंद्र सरकार पहले की तरह 1.16% की सब्सिडी देगी।

सीजेपी आंदोलन : वांगचुक का रक्त शर्करा स्तर गिरा, दीपके ने की कॉकरोचों के साथ 'चाय पर चर्चा'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का रक्त शर्करा स्तर गिरकर 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रह गया है और उनका रक्तचाप भी बृहस्पतिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनके अनशन के पांचवें दिन निम्न बना रहा। इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कॉकरोचों के साथ चाय पर चर्चा पहल की घोषणा की जिसका मकसद प्रदर्शनकारियों से आंदोलन का विस्तार करने के बारे में सुझाव लेना है। आंदोलन शुरू हुए 13 दिन हो चुके हैं।

दीपके ने 'एक्स' पर वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ रही है और यदि उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। दीपके ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। उनका शुगर लेवल गिरकर 60 रह गया है और रक्तचाप भी बहुत कम है। यदि सोनम सर को कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग भी दोहराई। दीपके ने कॉकरोचों के साथ चाय पर चर्चा की और कहा कि इसका उद्देश्य यह जानना है कि हम इस आंदोलन को और बेहतर तथा बड़ा कैसे बना सकते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) से जुड़े छह छात्र भी प्रदर्शन स्थल पर अलग मंच से अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखे हुए हैं। एक दिन पहले आइसा ने कहा था कि अनशन कर रहे छात्रों की सेहत बिगड़ रही है। संगठन का दावा है कि जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव दानिश का रक्त शर्करा स्तर गिरकर 61 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रह गया है, जबकि आमीन और दीपक कुमार को भी चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण अनशन जारी न रखने की सलाह दी है।

पत्थर की खदान में विशाल चट्टान गिरने से आठ श्रमिकों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु दक्षिण तालुक में बृहस्पतिवार को पत्थर की एक खदान में विशाल चट्टान गिरने से आठ श्रमिकों की मौत हो गई जिनमें अधिकांश बिहार के निवासी थे। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा तड़के बेंगलूरु शहर और बेंगलूरु दक्षिण जिले की सीमा पर स्थित मदापट्टन में हुआ। उसने बताया कि सभी एक 'स्टोन क्रशर' पर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। पुलिस ने बताया कि चट्टान के गिरने के बाद ये सभी उसके नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब मजदूर खदान में काम कर रहे थे। इस हादसे में घायल हुए लोगों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बेंगलूरु दक्षिण तालुक के मदापट्टन में सात मजदूरों की मौत की घटना अत्यंत दुखद है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा करना खदान मालिकों का कर्तव्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई करेगी।'' यशवंतपुर के विधायक एस.टी. सोमशेखर के अनुसार, आठवें श्रमिक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह पिछले कई वर्षों से इस अवैध खनन'' के संबंध में शिकायत कर रहे हैं और उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था।

सोमशेखर ने कहा कि कुछ समय पहले खदान मालिकों द्वारा किए गए विस्फोट के कारण एक तेंदुए की भी मौत हो गई थी। विधायक ने संवाददाताओं से कहा, इन अवैध गतिविधियों में पुलिस, वन विभाग और खनन विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जिन पर मामला दर्ज कर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आठ लोगों की मौत एक गंभीर मामला है। उस जगह पर काम करने वाले लोगों के अनुसार, मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि कुछ घायलों की हालत नाजुक है। उन्होंने आशंका जताई कि कई घायल अपंग हो सकते हैं। घायलों की सटीक संख्या की अभी पुष्टि की जा रही है। लेकिन शुरुआती सूचना में कई मजदूरों के घायल होने की बात सामने आई है।

चट्टान गिरने की घटना के बाद बचाव दल और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे तथा राहत कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है। घटनास्थल पर मौजूद एक श्रमिक ने बताया कि वहां बिहार और उत्तरी कर्नाटक के लगभग 18 कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी करीब 40 फुट की ऊंचाई से एक विशाल चट्टान श्रमिकों पर आ गिरी। दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है वहां मौजूद वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गए और एक ट्रैक्टर के पुर्जे-पुर्जे बिखर गए।

यह जानकारी मिली है कि मृतकों में अधिकांश बिहार के निवासी थे और उनके परिवारों को सूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतकों और घायलों के परिजनों तथा परिचितों की चीख-पुकार और विलाप से पूरे इलाके में मातम छा गया। पुलिस ने बताया कि चट्टान गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या खदान में कोई लापरवाही बरती गई थी या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया था।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

बेंगलूरु। बेंगलूरु जिले में एक पत्थर की खदान में हुए भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में सात मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, कर्नाटक के बेंगलूरु शहरी जिले में पत्थर की खदान में हुए हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उपराष्ट्रपति

सीपी राधाकृष्णन ने भी हादसे पर शोक जताते हुए कहा, कर्नाटक के बेंगलूरु शहरी जिले में पत्थर की खदान में हुई दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियों का जाना बेहद पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कर्नाटक के बेंगलूरु शहरी जिले में पत्थर की खदान में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की खबर से बेहद दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 52 आपराधिक मामले वापस लेने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य मंत्रिमंडल के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत 52 आपराधिक मामलों में मुकदमा वापस लिया जाना था। इनमें 2022 के अलंद लाडले मशक दरगाह दंगे से जुड़े मामले भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति के.एस. हेमलेखा की पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के लिए राज्य द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 का इस्तेमाल करना, उच्च न्यायालय के पहले के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने राज्य सरकार और अभियोजन निदेशालय को नोटिस जारी किया और उन्हें दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील गिरीश भारद्वाज ने अदालत में याचिका दायर करके 27 मई के उस सरकारी आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था जिसमें सरकारी वकीलों को न्याय के हित में राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था।

उन्होंने यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि 21 मई के मंत्रिमंडल के फैसले और उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड मंगाकर उन्हें रद्द किया जाए, और साथ ही न्याय के हित में उसके आधार पर जारी किए गए सभी आदेशों, अधिसूचना, सूचनाओं और निर्देशों को भी रद्द किया जाए। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 21 मई को किसानों और कन्नड़-समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों सहित 52 आपराधिक मामलों में मुकदमा वापस लेने का फैसला किया। कलबुर्गी जिले के अलंद में हुई हिंसा से जुड़े कम से कम आठ मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया। विपक्षी भाजपा ने अलंद हिंसा से जुड़े मामलों को वापस लेने के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार ''तुष्टिकरण की राजनीति'' के लिए कानून के शासन से समझौता कर रही है। अलंद का मामला एक मार्च, 2022 का है, जब भाजपा के कुछ कार्यकर्ता दरगाह के अंदर शिवलिंग का शुद्धिकरण अनुष्ठान करना चाहते थे; उनका आरोप था कि शिवलिंग को अपवित्र किया गया था।

तंउविबो OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी)

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं-2, सेक्टर-73, नोएडा-201301

No. AD/30/2024-ADM- Part (2) दिनांक : 24 जून, 2026

1. तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त/सांविधिक निकायों से योग्य उम्मीदवारों से उचित माध्यम से 7वें सीपीसी के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन स्तर-13 पर वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफ एंड सीएओ) और वेतन स्तर-06 पर आशुलिपिक ग्रेड-सी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

2. ओआईडीबी में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21वाँ दिन होगी।

3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार नियुक्ति पी एंड पीडब्ल्यू विभाग, केंद्र सरकार द्वारा तत्काल समावेशन से छूट दिए जाने के अधीन होगी।

4. योग्यता के मानदंडों, वैकेंसी सर्कुलर और अन्य विवरणों के लिए कृपया OIDB की वेबसाइट www.oidb.gov.in पर जाएं। यदि वेबसाइट काम नहीं कर रही है या उस तक पहुँचा नहीं जा पा रहा है, तो जरूरी जानकारी mgr.admn.oidb@nic.in पर लिखकर प्राप्त की जा सकती है।

5. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी शुद्धि/परिशिष्ट/निरस्तीकरण आदि केवल ओआईडीबी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ओआईडीबी वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

प्रबंधक (पी एंड ए)
ओआईडीबी, नोएडा

CBC 33113/11/0004/2627

भारत सरकार
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7वीं मंज़िल,
प्लाट झ-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी. मानेसर,
गुड़गाँव, हरियाणा - 122050.
ईमेल: roc.cpace@mca.gov.in

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6 सार्वजनिक सूचना

कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2026-27/617 दिनांक : 23/06/2026

संदर्भ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (50) कंपनियों के नाम कर्नाटक राज्य से हटाने के मामले में:

S.NO	Work Item	CIN	Company Hindi Name
1	AC3974409	U85100KA2022PTC164189	बेलगाम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	AC3975439	U74999KA2019PTC121472	एचकेबी रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AC3954736	U40102KA2012PTC065708	एसीएस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
4	AC3946900	U46909KA2025PTC204303	इकोएलीट एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AC4000596	U72900KA2008PTC047028	नाइल माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AC3921285	U73100KA2025PTC202820	सीक सिंपल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AC3922923	U52609KA2022PTC162641	वीजीपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AC4027884	U62020KA2024PTC190305	अज्जमपुर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
9	AC3907721	U31900KA2021PTC152823	ऑटोनेटिक कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AC3910720	U62013KA2024PTC185798	एमगस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AC3893755	U31500KA2008PTC048475	रस्मी लाइटिंग एंड एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
12	AC3867647	U72900KA2021PTC148033	एमएसवीआर टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AC3850567	U93000KA2016PTC097847	किंग्समैन सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
14	AC3660107	U74999KA2017PTC102797	वेप्रिम डेटा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AC3955059	U74999KA2017OPC108995	अस्मिथे टेक्निकल सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
16	AC4025568	U55209KA2018PTC116000	सुआइला डेलिकेसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
17	AC4008149	U68200KA2024PTC185251	सोनस प्रॉप कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
18	AC3983544	U80301KA2022PTC163428	ई360बस्ता एडटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	AC3870925	U62020KA2025OPC198593	हेक्साफोर टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
20	AC3761734	U80300KA2020PTC136424	एफडब्ल्यूडी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
21	AC3961614	U74999KA2020PTC134920	लाइकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
22	AC3986605	U62099KA2023PTC179822	नामोटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
23	AC3962801	U62099KA2023PTC171489	पारेख्स टेक मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AC3973056	U74999KA2021PTC151938	आर.एस. इन्फ्रालाइन प्राइवेट लिमिटेड
25	AC3958556	U70200KA2023PTC182287	जिशान सिरसांगी प्राइवेट लिमिटेड
26	AC3981162	U69100KA2025PTC198172	अनावो लीगल प्राइवेट लिमिटेड
27	AC3954336	U70109KA2022PTC164228	नेबरिंग नेस्ट्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
28	AC3906589	U01100KA2022PTC157422	केन्र्स एंड मार्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
29	AC3897892	U62091KA2024PTC183011	सिप्लसप्लस सेमिकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड
30	AC3888709	U72900KA2022PTC160689	आथन्ना टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
31	AC3882638	U86100KA2026PTC218426	प्रसन्ना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
32	AC3891417	U72200KA2018PTC109667	मिलोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
33	AC3845381	U28199KA2024OPC189953	शोइनोइज़ रिसर्च (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
34	AC3859831	U72900KA2022PTC163099	सीबीकोर आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
35	AC3808073	U55100KA2019PTC130821	बटर स्टोरीज़ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
36	AC4006894	U70100KA2016PTC085297	रेया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
37	AC3468965	U85300KA2018PTC117226	सिशा फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
38	AC3996916	U52100KA2015PTC084691	प्राइसजेट रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AC3477190	U74999KA2020PTC134393	टास्कऑपरेशन ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
40	AC3483932	U72200KA2018PTC115845	सेड्युलस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
41	AC3811013	U01409KA2021PTC149440	ग्रोवांटा प्राइवेट लिमिटेड
42	AC3773996	U62020KA2024PTC184153	यूनीट्रूथ कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
43	AC3780905	U72900KA2017PTC103781	सौकोस रोबोट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
44	AC3875498	U80903KA2019PTC121701	प्रेडिकल प्रिपरेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
45	AC3890643	U93093KA2016PTC094327	रसुलास्टोरी प्राइवेट लिमिटेड
46	AC3720232	U70200KA2024OPC189508	रॉयस बरेट्टो (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
47	AC3727771	U68100KA2025PTC201268	ट्विफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AC3734125	U72900KA2021PTC151665	टेकसॉल्व टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
49	AC3679196	U74999KA2018PTC119252	ह्यूगो एज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
50	AC3569927	U63090KA2016PTC087068	हॉपएनमूव प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अत: कंपनी रजिस्ट्रार से अपना / अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकान तिर्की
उप - पंजीयक
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र

CBC 07123/11/0270/2627

इसरो isro

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो)
द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी)
निर्माण एवं अनुरक्षण समूह
80 फीट रोड, एचएएल II चरण, बेंगलूरु-560008 फोन: 080-25037203/080-2503214

दिनांक: 02.07.2026

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए नग दर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं	कार्य का नाम व निविदा विवरण	निविदा का अनुमानित मूल्य	अग्रदाय रकम जमा (ईएमडी)	कार्य समापन अवधि
1	एलपीएससी (बेंगलुरु) परिसर में सिविल अनुरक्षण कार्यों हेतु अवधि अनुबंध NIT No. LPSC(B)/CMD/03/3021/C/MI/010/2026-27 दिनांक: 02.07.2026	रु. 10.00 लाख	रु. 20,000/-	12 माह
2	एलपीएससी (तुमकुरु) परिसर में सिविल अनुरक्षण कार्यों हेतु अवधि अनुबंध NIT No. LPSC(B)/CMD/03/3021/C/MI/011/2026-27 दिनांक: 02.07.2026	रु. 10.00 लाख	रु. 20,000/-	12 माह
3	एलपीएससी (बेंगलुरु) परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्यों हेतु अवधि अनुबंध NIT No. LPSC(B)/CMD/03/3021/C/MI/012/2026-27 दिनांक: 02.07.2026	रु. 5.00 लाख	रु. 10,000/-	12 माह
4	एलपीएससी (तुमकुरु) परिसर में विद्युत अनुरक्षण कार्यों हेतु अवधि अनुबंध NIT No. LPSC(B)/CMD/03/3021/C/MI/013/2026-27 दिनांक: 02.07.2026	रु. 5.00 लाख	रु. 10,000/-	12 माह

निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि : 02.07.2026 को 18.30 बजे से 14.07.2026 को 23.59 बजे तक
बोली स्पष्टीकरण : 02.07.2026 को 20.00 बजे से 15.07.2026 को 10.00 बजे तक
बोली स्पष्टीकरण के जवाब देने की अंतिम तारीख : 16.07.2026 को 17.00 बजे तक
निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय : 17.07.2026 को 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की नियत तारीख और समय : 17.07.2026 को 11.30 बजे से

पात्रता मानदंड और अन्य ब्यौरे के लिए इच्छुक निविदाकार विस्तृत सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी) देंखे जिसे वेबसाइट www.tenderwizard.com/ISRO से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली प्रपत्र औप अन्य ब्यौरे वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। www.isro.gov.in, www.lpsc.gov.in

ह/- प्रमुख सीएमडी, एलपीएससी(बी)

राज्य में जारी खनन गतिविधियां को लेकर जांच की जाएगी : शिवकुमार

बेंगलूरु। बेंगलूरु दक्षिण तालुक में हुए खदान हादसे में आठ मजदूरों की मौत के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेंगे कि राज्य में खनन गतिविधियां मानदंडों के अनुसार की जा रही हैं या नहीं। इस हादसे में मारे गए श्रमिकों में अधिकतर बिहार के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने हादसे में लोगों की मौत होने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, ''हम पूरे राज्य में खदान गतिविधियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो।'' शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है। अधिकारी वहां मौजूद हैं और अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''शुरुआती सूचना में सात लोगों की मौत की बात सामने आई है । पहली रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह घटना विस्फोट के कारण नहीं, बल्कि मिट्टी के कटाव के कारण हुई है। मैं इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट लूंगा।'' जब पत्रकारों ने उनसे अनुग्रह राशि के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुआवजा इस समय पहली प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा, ''हम परिवारों को निश्चित रूप से मुआवजा प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन मेरी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कर्नाटक में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।'' इस बीच, यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने पुष्टि की कि आठवें मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने यहां पत्रकारों से कहा कि वह इस मामले में पूरी जानकारी जुटाएंगे और यदि राजस्व विभाग से संबंधित कोई भी बात सामने आती है, तो वह तुरंत कार्रवाई करेंगे। परमेश्वर के पास राजस्व विभाग का भी प्रभार है। उन्होंने कहा, ''हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि ये मंजूरियां कौन देता है।

HSFC इसरो isro

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
मानव अंतरिक्ष उड़ान केन्द्र (एचएसएफसी)
निर्माण एवं रखरखाव समूह (सीएमजी)
देवनहल्ली, कर्नाटक-562164, दूरभाष: 080-29916308

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

क्र. सं.	कार्य का विवरण एवं एनआईटी संख्या	निविदा की अनुमानित लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अवधि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	धरोहर राशि (ईएमडी)
01	एचएसएफसी, मराठाहल्ली, बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण सुविधा में सिविल, पीएच, विद्युत, वातानुकूलन, उद्यानिकी एवं हाउसकीपिंग कार्यों के अनुरक्षण हेतु अनुबंध। HSFC/CMG/MM/C/175/2026-27, दि : 02.07.2026	रु. 160.27 लाख	24 माह	03.07.2026 को 11.00 बजे से 15.07.2026 को 23.30 बजे तक	17.07.2026 को 10.30 बजे तक	17.07.2026 को 11.00 बजे तक	रु. 3,20,540/-
02	एचएसएफसी (मराठाहल्ली एवं देवनहल्ली), बेंगलुरु में विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु अवधि अनुबंध। HSFC/CMG/MM/E/176/2026-27, दि : 02.07.2026	रु. 15.00 लाख	12 माह				रु. 30,000/-
03	मौजूदा बोरवेल पर 7.5 एचपी सबमर्सिबल पंप की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं चालू करना। HSFC/CMG/MM/C/E/177/2026-27, दि : 02.07.2026	रु. 7.23 लाख	02 माह				रु. 14,460/-

निविदा दस्तावेज www.tenderwizard.com/ISRO से टेंडर विज़ार्ड में पंजीकरण कर तथा निविदा प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके डाउनलोड किए जा सकते हैं। विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इच्छुक निविदादाता पात्रता मानदंड एवं अन्य विवरणों हेतु विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) वेबसाइट www.isro.gov.in पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी तथा निविदा दस्तावेज खरीदने के लिए www.tenderwizard.com/ISRO पर जाएँ।

ह/- प्रमुख, सीएमडी, एचएसएफसी

खदान हादसा; मज़दूरों की मौत के लिए कंपनी ज़िम्मेदार

बेंगलूरु। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मगदी रोड पर मदपटना गांव के पास एक पत्थर की खदान में हुए हादसे में मज़दूरों की मौत पर गहरा दुख जताया और खदान मालिकों और सरकार की लापरवाही पर गुस्सा जताया। बेंगलूरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा; मदपटना गांव में खदान में काम कर रहे मज़दूरों की मौत हो गई है। भगवान मरने वालों की आत्मा को शांति दे। सभी मरने वाले प्रवासी मजूदर हैं।

29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन दूसरा दिन

'विकसित भारत2047' की संकल्पना को साकार करने का माध्यम बन रहे हैं प्रदेश के तकनीकी नवाचार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित हुए प्लेनरी सत्र-5 में 'सिटिजन सेंट्रिक गवर्नेंस: इन्क्लुसिव गवर्नेंस' विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। सत्र में तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ, जवाबदेह एवं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। सत्र की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, राजस्थान श्री अरिजीत बनर्जी ने कहा कि राजस्थान जैसे विशाल राज्य में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिकतम सेवाएं डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना है। उन्होंने देश के पहले डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक 'डिजि-वन' के बारे में बताया कि विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए साझा डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिससे विभाग समन्वित रूप से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 'हरियालो राजस्थान मिशन' का उल्लेख करते हुए बताया कि यह जनभागीदारी आधारित अभियान है, जिसमें नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं तथा क्यूआर कोड के माध्यम से भी पौधों की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री राजन विशाल ने कहा कि नागरिक-केंद्रित सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि शासन व्यवस्था के केंद्र में नागरिक हो। उन्होंने कहा कि बेहतर नीतियां बनाने के लिए सही और भरोसेमंद आंकड़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न विभागों के बीच सुरक्षित डेटा साझा करने की व्यवस्था विकसित कर शासन को प्रतिक्रियात्मक के बजाय सक्रिय बनाया जा सकता है। उन्होंने एग्रीस्टैक, आईएफएमएस तथा सिंगल होल्डिंग प्रोक्योरमेंट पोर्टल (एसएचपीपी) जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हुई हैं। साथ ही उन्होंने नीति निर्माण एवं सेवा वितरण में एआई के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता जताई।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट ङ्कसचिव एवं आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता ने कहा कि नागरिक-केंद्रित शासन का आधार समान अवसर और पारदर्शी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार लगभग प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग कर नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने 'राजकाज', 'राजस्थान संपर्क पोर्टल', 'जन सूचना पोर्टल' तथा 'ई-मित्र' जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि 'राजकाज' के माध्यम से सरकारी अधिकारियों द्वारा फाइलों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय का भी आकलन किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और जवाबदेही बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के तकनीकी नवाचार 'विकसित भारत2047' की संकल्पना को साकार करने का माध्यम बन रहे हैं। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचारङ्क विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

टोंक की जिला कलक्टर श्रीमती टीना डाबी ने कहा कि राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से विस्तृत राज्य में सेवाओं की दूरी नागरिक नहीं, बल्कि सरकार तय करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं उनके निकट ही उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने 'जन आधार' को नागरिक-केंद्रित शासन की मजबूत आधारशिला बताते हुए कहा कि एकल पहचान के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने 'पोषण ट्रैकर' का उदाहरण देते हुए बताया कि तकनीक के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण की नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 'ई-मित्र' के माध्यम से नागरिक अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर ही अधिकांश सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 181 हेल्पलाइन के जरिए कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर उसकी प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि सेवा वितरण में शेष अंतराल को दूर करने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन भी कर रही है, ताकि सरकारी सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंच सकें। सत्र का संचालन करते हुए प्राइमस पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक श्री समीर जैन ने कहा कि राजस्थान देश में तकनीक को व्यापक स्तर पर तेजी से अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक और नवाचार के प्रभावी उपयोग के माध्यम से विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

विशेषज्ञों ने जनस्वास्थ्य के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जनजागरूकता को बताया अहम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। डॉक्टर केवल मरीजों का उपचार करने वाले नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के मार्गदर्शक भी होते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बुधवार को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर यहां राजस्थान अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। कार्यक्रम में कई चिकित्सकों ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जनजागरूकता के महत्व पर जोर दिया। अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. एस. एस. अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टरों की भूमिका केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है।

उन्होंने कहा, डॉक्टर केवल बीमारियों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि उम्मीद, विश्वास और मानवता की भी रक्षा करते हैं। समाज का स्वस्थ भविष्य डॉक्टरों की निष्ठा, सेवा और करुणा पर निर्भर करता है। अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि आज के दौर में डॉक्टर केवल देखभाल करने वाले नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने कहा, आधुनिक चिकित्सा का ध्यान केवल उपचार पर ही नहीं, बल्कि बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने पर भी होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान हर्पीज जोस्टर और हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोगों के बीच संबंध पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. दिनेश माथुर ने कहा कि हालिया शोध से पता चला है कि यह संक्रमण केवल तंत्रिकाओं को ही नहीं, बल्कि रक्त वाहिकाओं सहित पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, जिससे हृदय संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है। मुख्य वक्ताओं में डॉ. रवीन्द्र सिंह राव ने कहा कि विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि हर्पीज जोस्टर संक्रमण के बाद दिल का दौरा और मस्तिष्काघात का खतरा बढ़ सकता है।

डॉ. कैलाश चंद्र और डॉ. ए. डी. माथुर ने भी इस विषय पर अपने विशिष्ट विचार साझा किए। इस अवसर पर डॉ. वीणा आचार्य द्वारा तैयार जनस्वास्थ्य पोस्टर 'स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ राष्ट्र' का भी विमोचन किया गया।

राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लोगों का प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर बुधवार को जयपुर में प्रदर्शन कर रहे घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के पुलिस पर पथराव करने से यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आयोजित 'महापंचायत' में शामिल होने के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में एकत्रित हुए थे। शाम को महापंचायत समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की घोषणा की।

पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करते हुए मार्ग पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।पथराव की घटना में कुछ पुलिसकर्मियों सहित करीब 12 व्यक्ति लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बाद में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। हिंसा के सिलसिले में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। जूली ने कहा, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति समुदाय के सदस्यों पर, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज, आंसू गैस और बल प्रयोग किया जाना बेहद निंदनीय है।

उन्होंने कहा, अब सरकार की हर समस्या का जवाब केवल लाठीचार्ज, आंसू गैस और दमन तक सीमित दिखाई देता है। संवाद और समाधान के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। जूली ने मांग की कि राज्य सरकार विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता शुरू करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले।

बधाई

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राज्य सभा सदस्य श्रीमती अलका गुर्जर ने गुरुवार को लोकभवन पहुंचकर मुलाकात की। राज्य सभा सदस्य बनने के बाद राज्यपाल से उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल श्री बागडे ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

स्मार्ट पुलिसिंग में एआई की भूमिका पर हुआ मंथन, एआई से पुलिसिंग हो रही है रिएक्टिव से प्रिवेंटिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दूसरे दिन गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 'एआई फॉर स्मार्ट पुलिसिंग एंड पब्लिक सेफ्टी' विषय पर प्लेनरी सत्र आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री गोपेश अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा कि कृत्रिम एआई के उपयोग से पुलिसिंग अब प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिव) से निवारक (प्रिवेंटिव) स्वरूप की ओर बढ़ रही है। इससे अपराधों में कमी आई है तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया समय भी घटा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के सभी राज्यों की पुलिस एआई का उपयोग कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई को मानव संसाधन के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि पुलिसिंग में 'फोर्स मल्टीप्लायर' के रूप में देखा जाना चाहिए।

सत्र के पैनलिस्ट डॉ. अमनदीप कपूर, निदेशक, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जयपुर ने कहा कि एआई के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने एआई, ब्लॉकचेन, डेटा कंप्यूटिंग, सीसीटीएनएस 2.0, ई-साक्ष्य, एजेंटिक एआई, एज-आधारित एलएलएम, म्यूल हंटिंग ऐप तथा डार्क वेब जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि ये तकनीकें आधुनिक पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित एवं व्यापक स्तर पर एआई के उपयोग के लिए संप्रभु, जिम्मेदार और स्वदेशी एआई का विकास आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बीपीआरएंडडी इस दिशा में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा आवश्यक प्रणालियां विकसित करने का कार्य कर रहा है।

पैनलिस्ट श्री कोम्मी किशोर, पुलिस अधीक्षक, एलुरु (आंध्र प्रदेश) ने कहा कि वर्तमान समय में सभी पुलिस बलों का एआई से परिचित होना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस द्वारा उपयोग में लाई जा रही विभिन्न जांच संबंधी एप्लीकेशंस का उल्लेख करते हुए भाषा अनुवाद की उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से दोषसिद्धि (कन्विक्शन) की दर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में एआई के बढ़ते उपयोग के बीच बहुत तेजी और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने के बजाय संतुलित एवं चरणबद्ध तरीके से इसे अपनाना आवश्यक है। बिना उचित नियमन के नवाचार जोखिमपूर्ण हो सकता है तथा पुलिस जांच में 'एल्गोरिथिक बायस' से बचना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एआई का उद्देश्य पुलिसिंग को प्रोएक्टिव बनाना होना चाहिए, केवल प्रिडिक्टिव नहीं। पैनलिस्ट श्री सलमान ताज, निदेशक, सीडीटीआई, हैदराबाद ने कहा कि पुलिसिंग से संबंधित अधिकांश डेटा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिखरा हुआ है, जिसे एकीकृत कर डेटा फ्यूजन सेंटर के माध्यम से एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बी जी राम जी के लिए प्रदेश में 12 हजार 636 करोड़ का प्रावधान : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने गुरुवार को आंध्रप्रदेश के तिरूपति से विकसित भारतरोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी योजना के राष्ट्रीय शुभारंभकार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मण्डी से इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबी जी राम जी योजना के राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिएप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन मेंवीबी जी राम जी योजना लाई गईहै। प्रधानमंत्री का स्पष्ट विश्वास है कि गांवों को विकसित बनाकर ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है। किसान की समृद्धि, श्रमिक के सम्मान और गांव की आत्मनिर्भरता से भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा।यह योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथजल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास का समग्र राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिनयह अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पाया।मनरेगा के तहत अधिकांश काम में अस्थायी सड़कों, आधी-अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी खुदाई जैसे कार्य होते थे।

गहलोत ने मुख्यमंत्री को बकाया भुगतान पर तत्काल पत्र लिखा, वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य की भुगतान व्यवस्था में कथित गड़बड़ी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बकाया राशि जारी करने में देरी से कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, मरीजों, ठेकेदारों और समाज के कई अन्य वर्गों पर बुरा असर पड़ा है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 'अर्जेंट' (अति आवश्यक) लिखकर एक विस्तृत पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने गंभीर होते वित्तीय संकट और प्रशासनिक कामकाज ठप होने की स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक विभाग या योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लगभग हर वर्ग पर इसका असर पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे भुगतान समय पर जारी करने और प्रभावित वर्गों को राहत देने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि कर्मचारी, पेंशनभोगी, दुर्घटना पीड़ितों के परिवार, अस्पताल, दवा आपूर्तिकर्ता और छोटे ठेकेदार सभी अपने वाजिब बकाया भुगतान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।उन्होंने स्थिति को अभूतपूर्व बताते हुए कहा, राज्य के इतिहास में वित्तीय कुप्रबंधन का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया। गहलोत ने बताया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपए का भुगतान कई महीनों से अटका हुआ है। उन्होंने बताया कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसे मानवाधिकारों से जुड़ा मामला मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने आगे कहा कि कई अस्पतालों ने या तो इस योजना के तहत अपनी सेवाएं कम करने की धमकी दी है या फिर समझौतों से पीछे हटने की बात कही है।उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हालात

में, कैशलेस इलाज के वादे के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और रिइम्बर्समेंट में भी अनिश्चित समय तक देरी हो रही है।

गहलोत ने 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी/आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' में हो रही देरी का भी जिक्र किया, जिसके तहत पात्र परिवारों को दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों मामलों में मंजूरी मिलने के बावजूद लाभार्थियों को पेमेंट नहीं मिला है, जिससे शोक-संतप्त परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पत्र में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भुगतान में देरी पर भी चिंता जताई गई है। गहलोत ने कहा कि जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे बकाया भुगतान रिटायरमेंट के बाद महीनों तक नहीं मिल रहे हैं, जबकि ये कर्मचारियों का हक है। उन्होंने यह भी बताया कि कई जिलों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी हुई है, जिससे बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों पर असर पड़ रहा है। गहलोत ने ट्रेजरी से मंजूर हो चुके बिलों के पेमेंट में हो रही देरी की ओर भी इशारा किया, जिससे सड़कों, पीने के पानी की सप्लाई और दूसरे सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि छोटे ठेकेदारों को अपने बकाया भुगतान की ओर ध्यान दिलाने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन देने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि इस स्थिति ने उनकी आजीविका और रोजगार पर बहुत बुरा असर डाला है। इस स्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए गहलोत ने कहा कि भुगतान का संकट केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि राज्य के लाखों परिवारों की गरिमा और आजीविका का सवाल है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि वे पेमेंट सिस्टम को बहाल करने और सभी विभागों व योजनाओं में बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तुरंत और निर्णायक कदम उठाएं।

चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हुई, 'कलंक' के साथ नहीं रहेंगे

अयोध्या/भाषा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से कहा है कि उनकी अयोध्या में सेवा पूरी हो गई है और वह कथित राम मंदिर दान गबन विवाद से जुड़े कलंक के साथ नहीं रहेंगे। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि फिलहाल एकांतवास में रह रहे राय ने यह भी कहा कि उनके साथ 'विश्वासघात' हुआ है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि उनका इशारा किसकी ओर था। यह घटनाक्रम राम मंदिर के दान में कथित गबन के विवाद और ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की वकीलों के एक वर्ग की मांग के बीच आया है।

सूत्रों ने कहा कि राय और उनके साथ ही ट्रस्ट में अपने पद से इस्तीफा दे चुके अनिल मिश्रा का भविष्य छह जुलाई को अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दो-तिहाई बहुमत से तय होने की संभावना है। बैठक में ट्रस्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर खासकर पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल की सिफारिशों के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद : वकीलों ने ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अयोध्या/भाषा। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले में बृहस्पतिवार को विरोध मार्च निकाला और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता एवं ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य कृष्ण मोहन का नाम भी वकीलों द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। वकीलों ने अदालत परिसर से श्रीराम जन्मभूमि थाने तक मार्च निकाला और शिकायत सौंपकर मांग की कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस दौरान वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ वकीलों ने आरोप लगाया कि धक्का-मुक्की में उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। थाने पहुंचने पर कई वकील थाना प्रभारी के कार्यालय में इकट्ठा हो गए और तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिकायत की जांच कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। कालिका प्रसाद मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि बार एसोसिएशन ने कई नामजद व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा, एक लिखित शिकायत सौंप दी गई है। पांच लोग शिकायत की पावती लेने गए हैं। यदि हमें उसकी प्रति नहीं दी जाती है तो हमारा विरोध जारी रहेगा। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कृष्ण मोहन (पहले दर्ज शिकायत में शिकायतकर्ता) के नाम शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि श्रीराम जन्मभूमि थाना पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।'' उन्होंने कहा कि यदि पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती है तो बार एसोसिएशन आंदोलन शुरू करेगा। बार एसोसिएशन ने पहले घोषणा की थी कि वे इस मामले में आरोपियों का बचाव नहीं करेंगे और उनका प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखने वाले किसी भी वकील के लिए प्रति आरोपी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी। नगर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में फैजाबाद बार एसोसिएशन की ओर से शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है। इस बीच, राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन को लेकर जारी विवाद के मद्देनजर अयोध्या के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र कार्यालय, कारसेवकपुरम और ट्रस्ट से जुड़े अन्य प्रमुख परिसरों में सुरक्षा कड़ी की गई है। तीर्थ क्षेत्र कार्यालय में चार उपनिरीक्षकों की तैनाती की गई है, जबकि क्षेत्र में प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) की एक कंपनी भी तैनात की गई है।

राम मंदिर दान चोरी : लवकुश मिश्रा की पत्नी को अवैध मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण का नोटिस

अयोध्या/भाषा। अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने राम मंदिर दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी को उनके नाम पर बने घर के कथित अनधिकृत निर्माण पर नोटिस भेजा है, जबकि पुलिस ने कथित गबन मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। आधिकारिक और पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

एडीए सूत्रों के मुताबिक सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में इस मकान का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि मकान वाली जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी गई थी और विकास प्राधिकरण से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किए बिना निर्माण किया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने बुधवार को लवकुश मिश्रा के आवास की भी तलाशी ली और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। इस बीच, पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया कि जांचकर्ता आरोपी अविनाश शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कड़ी कर सकते हैं, जिसके पास से अब तक सबसे अधिक नकद बरामदगी हुई है।

साइबर धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल एक फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़

लखनऊ/भाषा। राजधानी के गोमतीनगर स्थित समिट भवन में कथित तौर पर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने वाले और साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करने के बाद हिरासत में लिए गए 119 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इनके कब्जे से 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए है। पुलिस प्रवक्ता ने इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।

प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साइबर प्रकोष्ठ और साइबर पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम समिट भवन की 11वीं मंजिल पर छापेमारी की, जहां दो कार्यालयों से कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। उनके अनुसार, कॉल सेंटर में मुख्य रूप से रात में काम होता था और कथित तौर पर डॉलर ऐप का उपयोग करके तकनीकी धोखाधड़ी और विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से पीड़ितों को धोखा दिया जाता था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कॉल सेंटर सोलारिस सॉल्यूशन नाम से चल रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में दो कथित ऑपरेशन मैनेजर शामिल हैं। इनमें अहमदाबाद निवासी ललित खैरजानी और विक्रम सिंह परमार हैं जो वर्तमान में गोमती नगर एक्सटेंशन में रह रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों को साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क, इसके पीड़ितों, कॉलिंग मॉड्यूल और वित्तीय लेनदेन से संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए तकनीकी और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

वेणुगोपाल का पीएम को पत्र, राम मंदिर मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच का आग्रह

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में किसी उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। वेणुगोपाल ने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण से करोड़ों भारतीय नागरिकों की आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभिक जांच में किसी ''संगठित गिरोह'' के सक्रिय होने और हर स्तर पर ''संस्थागत विफलताओं'' के संकेत मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कथित लूट संस्थागत संरक्षण के बिना संभव नहीं थी।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि नकदी गिनने वाले कर्मचारियों ने नियमित निगरानी व्यवस्था को दरकिनार कर नकदी और बहुमूल्य आभूषणों की चोरी की, जबकि इस कथित आपराधिक षड्यंत्र के सबूत मिटाने के लिए कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गबन और चोरी की शिकायतों को या तो नजरअंदाज किया गया या फिर दबा दिया गया।

भाजपा ने मनीष तिवारी की पोस्ट को कांग्रेस की अंदरूनी कलह से जोड़ा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि कांग्रेस फिर से ''टुकड़े-टुकड़े मोड'' में है और उन लोगों की पार्टी में कोई अहमियत नहीं है जो ''परिवार'' को सबसे ऊपर नहीं रखते। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पार्टी की पंजाब इकाई में नए कार्यकारी अध्यक्षों और विभिन्न चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्तियों में खुद को 'नजरअंदाज किए जाने' पर बृहस्पतिवार को कहा कि काश ! उनके पास व्यक्तियों और संस्थाओं की ''असुरक्षा'' का कोई 'एंटीडोट' (प्रतिरोधक) होता।

तिवारी को पंजाब कांग्रेस के हालिया संगठनात्मक पुनर्गठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के अनुसार, कांग्रेस कई राज्यों में अंदरूनी गुटबाजी का सामना कर रही है। पूनावाला ने एक वीडियो संदेश में कहा, कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच खींचतान से पार्टी बंट गई है। हमने राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच, छत्तीसगढ़ में और अब पंजाब में भी झगड़ा देखा है, जहां मनीष तिवारी ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पर खुलकर हमला किया है। उन्होंने दावा किया, ''कांग्रेस फिर से टुकड़े-टुकड़े मोड में है।''

पूनावाला ने दावा किया कि तिवारी वाला पूरा मामला दिखाता है कि वरिष्ठ नेताओं की कोई अहमियत नहीं है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो के मलाही पकरी स्टेशन का उद्घाटन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता गलियारे के तहत राज्य की राजधानी में मलाही पकरी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण भी किया, जिसमें वह उद्घाटन पट्टिका का अनावरण करते, फीता काटते और मलाही पकरी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए।

इसके बाद उन्होंने मेट्रो में यात्रा भी की। इस मौके पर सम्राट के साथ उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल अक्टूबर में पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया था।

करीब 3.6 किलोमीटर लंबे इस प्राथमिकता गलियारे के पहले चरण में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो सेवा संचालित की जा रही है। मलाही पकरी चौक स्टेशन इस सेवा से जुड़ने वाला नया स्टेशन है।

टीएमसी नेता के बेटे के कैफे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर निर्माण का आरोप

कोलकाता/भाषा। तृणमूल कांग्रेस नेता सौकत मुल्ला के बेटे के स्वामित्व वाले एक कैफे को बृहस्पतिवार को ध्वस्त कर दिया गया। कथित रूप से सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर इस कैफे का निर्माण किया गया था। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह कैफे पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित था जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मुल्ला के परिवार को कई बार नोटिस जारी कर कथित अवैध' निर्माण हटाने को कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

अधिकारी के अनुसार, 'अरानाएर कुले' नामक यह कैफे कथित तौर पर मतला नदी के रेतीले टापू/बालू क्षेत्र पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाया था। संचालन पूर्व विधायक सौकत मुल्ला के बेटे इमरान मोल्ला द्वारा किया जाता था। इस मामले पर सौकत के परिवार से संपर्क नहीं हो सका। जिला प्रशासन ने कैफे के मालिक को 29 जून तक निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्देश का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारी स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे।

ईडी ने एक्सालॉजिक से जुड़े धनशोधन मामले में सीएमआरएल के कार्यकारी निदेशक से पूछताछ की

कोच्चि/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएमआरएल और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी के स्वामित्व वाली एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की धनशोधन जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को सीएमआरएल के कार्यकारी निदेशक अनिल आनंद पणिक्कर से पूछताछ की।

अधिकारियों ने बताया कि पणिक्कर सुबह करीब साढ़े दस बजे यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय में पेश हुए। अधिकारियों ने कहा कि यह दूसरी बार है जब एजेंसी ने पणिक्कर से पूछताछ की है, जो कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के संस्थापक शशिधरन कार्था के दामाद हैं। ईडी पहले ही मामले के संबंध में सीएमआरएल के निदेशकों के साथ-साथ वीणा से भी दो बार पूछताछ कर चुकी है। जांच इस आरोप से संबंधित है कि सीएमआरएल ने एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उससे कोई सेवाएं लिए बिना 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एजेंसी के अनुसार, कार्था द्वारा संचालित एम्पॉवर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ईआईसीपीएल) ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये का ऋण भी दिया था, जबकि कंपनी कथित तौर पर समय पर राशि चुकाने में विफल रही थी।

उत्तराखंड में भारी बारिश केबीच पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट'; बदरीनाथ और केदारनाथ मार्ग प्रभावित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देहरादून/भाषा। उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को देहरादून समेत पांच जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। मौसम विभाग ने कहीं-कहीं भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया है। लगातार बारिश के बीच पहाड़ियों से मलबा और पत्थर गिरने के कारण चमोली जिले में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग पर एहतियातन वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उत्तराखंड में 30 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और बुधवार तक यह पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया। इसके बाद से देहरादून सहित कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश हो रही है।

देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। वहीं, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के लिए कहीं-कहीं भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक सतर्कता बरतने और एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले के मुनकटिया क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस मार्ग पर वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है।

'आतंकवादी, आतंकवादी ही होता है : हत्यारी विचारधारा' को जड़ से मिटाने के लिए भारत का आह्वान

संयुक्त राष्ट्र/भाषा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद को उचित ठहराने के लिए किसी भी शिकायत को आधार बनाए बिना इस ''हत्यारी विचारधारा'' को जड़ से मिटाने के मकसद से मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा है कि आतंकवादी, आतंकवादी ही होता है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा, ''भारत सीमा पार आतंकवाद का दशकों से शिकार रहा है। हमारे लोगों ने आतंकवाद की भारी कीमत चुकाई है- जानें गईं, परिवार बर्बाद हुए और समाज बिखर गए। इसी अनुभव ने भारत के इस रुख को आकार दिया है कि आतंकवाद को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।''

उन्होंने कहा, ''चाहे कोई भी शिकायत, राजनीतिक उद्देश्य या रणनीतिक गुणाभाग हो, आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की बिना किसी हिचकिचाहट के निंदा की जानी चाहिए।''

खान सर के खिलाफ अंजना ओम कश्यप के मुकदमे को अदालत ने मध्यस्थता के लिए भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'खान सर' के नाम से मशहूर शिक्षक फैसल खान और अन्य शिक्षकों के खिलाफ टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड और उसकी प्रबंध संपादक अंजना ओम कश्यप के मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर कथित मानहानि वाली पोस्ट से जुड़ा है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने चैनल और कश्यप से संयम बरतने को कहा, साथ ही खान सर से पत्रकार अंजना ओम कश्यप के बच्चों के बारे में की गई पोस्ट को हटाने को कहा।

अदालत ने आपसी सहमति से मामला सुलझाने की बात कहते हुए प्रतिवादियों से अपनी पोस्ट में इस्तेमाल की गई 'असंसदीय' बातों को हटाने पर विचार करने को कहा। खान सर के अलावा, इस मुकदमे में 'अभिनय मैथ्स' के संस्थापक अभिनय शर्मा, आईसीएस कोचिंग की सह-संस्थापक बबिता त्यागी और नैया पार एजुकेशन के अरविंद भदौरिया को भी प्रतिवादी बनाया गया है। वादी पक्ष के वकील ने कहा कि खान सर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी उजागर की है कि कश्यप के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं और उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने वकीलों से कहा, ''वे (वादी) संयम बरतेंगे। आप (खान सर) बच्चे के बारे में दी गई जानकारी हटा लें। उनसे बात करने की कोशिश करें और देखें कि जिन हिस्सों में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या उन्हें हटाया जा सकता है।'' अदालत ने मौखिक रूप से कहा, ''दोनों पक्षों को संयम बरतना होगा। आप (वादी के वकील) सुनिश्चित करें कि आपकी मुवक्किल संयम बरतें। और आप (खान सर) बच्चों के बारे में जानकारी देना बंद करें। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जो अदालत तक आना चाहिए। जब आप युवाओं को पढ़ा रहे हो, तो यह आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, सही बात है ना?''

वादियों और खान सर के वकीलों ने भरोसा दिलाया कि वे संयम बरतेंगे और बच्चों से जुड़ी किसी भी बात को हटा देंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा, थोड़ी जांच-पड़ताल के बाद ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष इन विवादों को आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं। अगर किसी वरिष्ठ मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है, तो दोनों पक्ष समझौते की शर्तों पर विचार करने को तैयार हैं। वे आज ही मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने को भी तैयार हैं।

अखिलेश ने सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की निंदा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर कथित रूप से अंडे फेंके जाने की घटना की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राजनीतिक ''हिंसा का माहौल'' पैदा का आरोप लगाया। लोकसभा में 37 सांसदों वाली सपा के अध्यक्ष यादव ने इस घटना को ''अत्यंत निंदनीय'' बताया और न्यायपालिका तथा लोकसभा अध्यक्ष से इसका तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जब वह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के दौरे पर थीं। आरोप है कि इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने शासन वाले राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ''हिंसा का विषैला वातावरण'' बना रही है तथा पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''इस नकारात्मक-प्रहारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और आक्रोशित है। यहां तक कि भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, वहां भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के ऊपर अगर ऐसा प्राणघातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा या फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद क्या होगा।''

यादव ने कहा, ''भाजपा के बड़े नेता तो सुरक्षा घेरे में खुद को बचा लेंगे लेकिन आम कार्यकर्ता को सड़क पर जनाक्रोश का शिकार होने के लिए छोड़ देंगे।'' उन्होंने न्यायपालिका और लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। तृणमूल मोइत्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पार्टी विधायक अलीफा अहमद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके और उनके खिलाफ नारेबाजी की। मोइत्रा कालीगंज के पलाशी में अहमद के घर पर तृणमूल की बैठक में शामिल होने गई थीं, तभी बाहर प्रदर्शनकारियों का एक समूह जमा हो गया और 'वापस जाओ' के नारे लगाने लगा। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने अंडे भी फेंके और चोर'' के नारे लगाए।

सुविचार

ज़िंदगी में अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसके पास अपनों का साथ है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

यूजरनेम फीचरः सुविधा या खतरे की खिड़की?

वॉट्सऐप ने जो यूजरनेम फीचर पेश किया, उससे सुरक्षा संबंधी कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर इस संबंध में उचित कार्रवाई की है। देश में करोड़ों लोग वॉट्सऐप का उपयोग करते हैं। अगर उक्त फीचर को लागू करते समय सुरक्षा संबंधी जोखिमों का आकलन नहीं किया गया तो भविष्य में साइबर अपराध की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यूजरनेम फीचर किसी उपयोगकर्ता को अपना फोन नंबर साझा किए बिना बातचीत करने की सुविधा देता है। इसकी विशेषताएं जानकर ऐसा लग सकता है कि यह फोन नंबर साझा करने की जरूरत को खत्म कर उपयोगकर्ता की निजता को मजबूत करेगा। इसके दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। यह फीचर सामान्य उपयोगकर्ताओं को कुछ सुविधाएं जरूर देता है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने की आशंका है। क्या होगा अगर साइबर अपराधी यूजरनेम फीचर का उपयोग करने लग जाएं? वे एआई की मदद से लोगों को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। सोचिए, इस फीचर का उपयोग करते हुए, साइबर अपराधी हर किसी का नकली परिचित या रिश्तेदार बनकर रुपए मांगने लग जाएं तो कितने बैंक खाते खाली होंगे? पिछले पांच वर्षों में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। अगर ऐसे अपराधियों को वॉट्सऐप पर यूजरनेम फीचर जैसी सुविधा मिल गई तो उनके लिए अपनी पहचान छिपाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। वे इस फीचर की मदद से बहुत ताकतवर होकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाएंगे और उन्हें मिनटों में कंगाल बनाएंगे। देश में ऐसे कई गिरोह हैं, जो लोगों को फंसाते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। यूजरनेम फीचर से उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। वे बदनाम करने की धमकियां देंगे और संबंधित व्यक्ति को नजर भी नहीं आएंगे।

हाल में एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी से वॉट्सऐप कॉल पर 10 लाख रुपए मांगे गए थे। साइबर ठग ने उन्हें अपना परिचय पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के सचिव के तौर पर दिया। उन्हें झांसा दिया गया कि आपकी मुलाकात उनसे कराई जाएगी। पदाधिकारी ने रुपए दे दिए। बाद में उन्हें ठगी का पता चला। अगर वॉट्सऐप का यूजरनेम फीचर लागू होता तो कई पदाधिकारी लपेटे में आते और ठगी की रकम करोड़ों में होती। पिछले महीने, देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से 7.8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। उनकी कंपनी के कर्मचारी को फर्जी संदेश भेजकर रकम मंगवाई गई थी। कर्मचारी को इसलिए शक नहीं हुआ, क्योंकि डीपी में पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नजर आ रहे थे। बस, गनीमत यह रही कि समय पर शिकायत करने से पुलिस ने चार करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत रुकवा दिया था। जब ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के मौजूदा फीचर्स का पहले ही इतना दुरुपयोग हो रहा है तो एक और फीचर को आनन-फानन में लागू करना कितना सुरक्षित रहेगा, जबकि विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं? साइबर अपराधी बड़े शातिर होते हैं। वे नए-नए हथकंडे अपनाकर तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब उन्होंने किसी मजबूत कंपनी को बड़ी आसानी से करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। जनवरी 2023 में एक मामले ने दुनिया के तकनीकी विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया था। एक व्यक्ति ने मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी जानी-मानी फार्मा कंपनी का अकाउंट बनाया। उसके बाद शुल्क देकर ब्लू टिक लिया। फिर, उसने घोषणा की- 'हम इंसुलिन मुफ्त देने जा रहे हैं।' इससे कंपनी के शेयर के भाव गिरे और उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। अगर वॉट्सऐप के यूजरनेम फीचर में साइबर ठगी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो कई कंपनियों को ऐसे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।

ट्वीटर टॉक

हथिनीकुंड बैराज से 295 किमी लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के ज़रिए राजस्थान में पानी पहुंचेगा। 34,102 करोड़ का यह बड़ा प्रोजेक्ट चूरू, सीकर, झुंझुनू और कई दूसरे ज़िलों को पीने का पानी देगा, साथ ही खेती, इंडस्ट्री और इलाके के विकास को भी नई रफ़्तार देगा।

-अर्जुनराम मेघवाल

खानाबदोश समुदाय हमारे सबसे कमज़ोर तबकों में से एक है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। राज्य सरकार यह समझने में नाकाम रही है कि झगड़ों और समस्याओं का असली समाधान सिर्फ़ बातचीत से ही निकल सकता है।

-अशोक गहलोत

लंदन में 34वें रेनडांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट अवॉर्ड जीतने पर अनुया स्वामी और पंकजा की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई।इस ऐतिहासिक उपलब्धि से अनुया स्वामी इस कैटेगरी में फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान पाने वाली पहली भारतीय फिल्ममेकर बन गई हैं।

-डीके शिवकुमार

प्रेरक प्रसंग

नियम सबके लिए है

ए बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाईस्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य-भार दिया गया था कि आनेवाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा-स्थल पर यथास्थान बिठा दे। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण-पत्र की माँग की। बेटे! मेरे पास तो निमंत्रण-पत्र नहीं हैं, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें अंदर मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान! मेरे कार्य में यदि स्वागत-समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएँगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण-पत्र होना ही चाहिए। भेद-भाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की।

सामयिक

श्रीराम जन्मभूमि दान में सेंध

अवधेश कुमार

मोबाइल : 9811027208

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संदेहों के घेरे में आने से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष और हजारों बलिदान तथा स्वतंत्रता के बाद भी लंबे न्यायिक संघर्ष से श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति हुई, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में उमड़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या से हिंदू या सनातन समाज की आस्था समझी जा सकती है। वहां के चढ़ावे और चंदे में भी लोग से सेंधमारी कर रहे हैं तो यह हम सबके लिए डूब मरने की बात है। धर्म की दृष्टि से यह महापाप है। श्रद्धालु मंदिरों में इसलिए दान देना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं और भावना यही रहती है कि इहलोक और परलोक दोनों जीवन अच्छे हो तथा किसी जन्म में हुते पाप या अपराध से क्षमा मिल जाए। हमारे धर्म में दान को यहां तप माना गया है। दान चोरी करने वाले के लिए तीनों लोक में बुरी गति की बात है। वर्तमान जीवन में इस तरह की सेंधमारी करने वाले को कोई भी सजा कम होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है, आगे भी जांच जारी है। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस उसके आधार पर छानबीन कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों व संदिग्धों से पूछताछ तथा ट्रस्ट एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से जानकारी भी ले रही है। विवेक का सामान्य तकाजा है कि हमें दोषियों या पापियों के संदर्भ में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कम से कम छानबीन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। किंतु यह ऐसा संवेदनशील मामला है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ीं हैं तथा पूरी जानकारी बाहर न होने के कारण अलग-अलग तरह से अटकलें लग रहे हैं। राजनेताओं के राजनीतिक बयानों और मीडिया की लगातार कवरेज से कुछ ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें सच तक पहुंचना लगभग असंभव है।

सच यह है कि श्रीराम जन्मभूमि चंदा चोरी मामले की वास्तविक जानकारी बयान देने वालों के पास बिल्कुल नहीं हो सकती। जितनी राशि बताई जा रही है पता नहीं उतना चंदा भी आया होगा कि नहीं। एक वरिष्ठ नेता का बयान है कि 20 हजार करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई। क्या श्रीराम मंदिर में इतने दान आए? कोई कह रहा है कि हमने चांदी फलां चीजें दीं और उसका आता-पता नहीं। यह जानकारी कहां से मिली कि उसका आता-पता नहीं है? क्या दान देने वाले को बार-बार बुलाकर दिखाया जाएगा कि आपने जो कुछ दिया था वह यहां रखा हुआ है? थोड़े शब्दों में कहे तो अतिवाद की सीमा को पार करने वाला वाले आरोप आ रहे हैं जिनका सच्चाई से लेना देना नहीं हो सकता। चूंकि चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं इसलिए राजनेताओं के सर्वाधिक निशाने पर वही हैं। गोपाल राव व अनिल मिश्रा दोनों संघ परिवार के संगठन से जुड़े रहे हैं इसलिए स्वाभाविक ही नेताओं के निशाने पर हैं। जिन नेताओं के पास स्वयं आय से अधिक संपत्ति दिखती है जो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने के बावजूद पद से त्यागपत्र देने को तैयार नहीं थे उनकी शुचिता और ईमानदारी की बात कौन सुनेगा? इसलिए इनक वक्तव्यों पर जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें भी दो राय नहीं कि चंदा का एक-एक पैसा सुरक्षित रहे इसके लिए जिस तरह की निगरानी होनी चाहिए उसमें कमी रही तभी यह संभव हुआ। आप किसी तरह की व्यवस्था कर लीजिए लालची मनुष्य उनमें से भी कोई न कोई खांच निकाल कर पाप और अपराध करते ही है। श्रीराम जन्मभूमि को महत्व मिलने के कारण उससे किसी तरह जुड़े ऐसे लोग जिनको समाज थोड़ा बहुत जानता है उनका सम्मान बढ़ा है। सामान्यत: प्रशासन भी ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है। इन दुष्टों ने इन सबका लाभ उठाया और महापाप किया। इनमें से कई की संपत्तियों और रहन-सहन के संबंध में आईं जानकारियां इसके प्रमाण हैं।

किंतु इसके लिए हम पूरे ट्रस्ट , मंदिर प्रबंधन प्रदेश और केंद्र सरकार सबको अपराधी नहीं मान सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तो दान की राशि की देखरेख करने नहीं जा सकते। निरपेक्ष लोगों का कहना है कि जैसे ही यह जानकारी सामने आने लगी ट्रस्ट के शीर्ष लोग सक्रिय हुए और संदिग्धों के घर जाकर जांच करने की कोशिश की। उनके अनुसार स्वयं चंपत राय ने ऐसा किया। प्रश्न उठाया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं जांच और छानबीन करने की बजाय पुलिस को मामला क्यों नहीं दिया? किसी संस्थान में कोई चोरी या गबन होता है तो पहले आरंभिक स्तर पर उसकी सच्चाई समझना आवश्यक होता है ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई होती है यह ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व का दायित्व था। हम आप यहां किसी को दोषमुक्त नहीं मान सकते पर मीडिया और नेताओं के बयानों से थोड़ा परे हटकर सच्चाई समझने की कोशिश करें तो पूरा निष्कर्ष वही नहीं आएगा जैसा बनाया गया है। चंपत राय अगर संलिप्त हैं तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। तथ्य यह भी है कि उन्होंने स्वयं प्रदेश सरकार को एसआईटी जांच करने के लिए लिए लिखित आग्रह किया, पुलिस को भी सूचना दी तथा सामने आने के दूसरे दिन ही जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया। इस कारण इस समय मंदिर प्रबंधन में इनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। इस सच को देखे बगैर हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

हमें बनाए जा रहे हैं वातावरण के खतरों को भी समझना चाहिए। मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्ति का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है और यह आवश्यक है। वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है जिससे भविष्य में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के सरकारी नियंत्रण में जा सकता है। सुझाव आ रहा है कि किसी पूर्व आईएएस अधिकारी के हाथों ट्रस्ट का संचालन दे दिया जाए। क्या इसके लिए केवल आईएएस उपयुक्त हो सकते हैं? आईएएस भ्रष्ट होते ही नहीं? धार्मिक संस्थाओं का संचालन धर्म क्षेत्र और समाज क्षेत्र के हाथों रहे यही उचित है। वह कोई भी हो सकता है। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि आगे जो ट्रस्ट बनेगा उसमें ऐसी घटना नहीं हो सकती? मूल बात मनुष्य का लालची होना है। भारत में शायद ही कोई मंदिर हो जहां चढ़ावे की पूरी की पूरी राशि संबंधित ट्रस्ट, प्रबंधन या मंदिर के खाते जाते हों। आप चलते-फिरते देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो दान पत्र में नहीं डालकर किसी के हाथों देते हैं और वो पैकेट में रख लेते हैं जबकि लिखा होता है कि सारा दान पेटी में ही डालें। इसका निदान तो हमारे धर्मनिष्ट, सत्यनिष्ठ और नैतिक होने में ही है। सनातन समाज में जब तक सनातनी के नाते दायित्व बोध और उसके प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं होगी तब तक किसी भी स्थल को चोरी से मुक्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए भविष्य में चंदे की गिनती और उनकी सुरक्षा को लेकर जितना संभव है सुरक्षित व्यवस्था हो किंतु अंतिम रास्ता तो समाज को मनुष्य के रूप में उनके जन्म और मृत्यु के उपरांत की स्थितियां और दायित्व व कर्मों का बोध कराने में ही है। जिस समाज का बहुत बड़ा वर्ग सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से दीर्घकाल से च्युत या भटका हो, अज्ञानी हो उनको फिर से धर्म दृष्टि देना आसान नहीं है, पर रास्ता तो यही है। धार्मिक दृष्टि से सचेतन समाज ही इसे रोक सकता है या ऐसी घटना होने पर सही वातावरण बनाए रखकर निदान निकल सकता है।

नजरिया

'इंडिया' नहीं, 'भारत': राष्ट्रीय अस्मिता का पुनर्जागरण

प्रणय कुमार

मोबाइल : 9588225950

'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' जैसे उद्घोष राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बने। प्रश्न है- यदि कोई 'इंडिया माता की जय' कहे तो क्या उससे वही भाव प्रकट होगा जो 'भारत माता की जय' से होता है? इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र की आत्मा सदैव 'भारत' नाम से ही स्वयं को अभिव्यक्त करती रही है। हाल के वर्षों में भी राष्ट्रीय जीवन में 'भारत' के प्रयोग की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ी है। जी-20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण-पत्रों में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' का प्रयोग हो अथवा अनेक सरकारी दस्तावेजों और संस्थानों द्वारा 'भारत सरकार' तथा 'भारत' शब्द को प्राथमिकता देना, ये सभी संकेत इस बात के द्योतक हैं कि देश की सांस्कृतिक चेतना अपने वास्तविक नाम की ओर स्वाभाविक रूप से लौट रही है।

देश के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की उपाधियों, अंकपत्रों, पत्राचार, निमंत्रण-पत्रों, साइन-बोर्डों तथा अन्य आधिकारिक अभिलेखों में 'इंडिया' के स्थान पर 'भारत' लिखने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्जागरण का उद्घोष है। यह परिवर्तन उस वैचारिक मंथन का परिणाम है, जो लंबे समय से शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रश्न पर देशभर में चल रहा है। हाल में मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ने अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में 'इंडिया' के स्थान पर 'भारत' लिखने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यपरिषद ने भी अपने आधिकारिक अभिलेखों में 'भारत' लिखने का प्रस्ताव पारित किया। 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा महाराष्ट्र के कम-से-कम सत्रह विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों ने इस दिशा में औपचारिक संकल्प पारित किए हैं। स्पष्ट है कि यह अब किसी एक विश्वविद्यालय का निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित एक व्यापक शैक्षिक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। इन निर्णयों के पीछे शैक्षिक क्षेत्र में सक्रिय 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' की वर्षों की सतत वैचारिक साधना और संवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। न्यास से जुड़े भारतीय भाषा मंच ने देशभर के विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के समक्ष निरंतर यह प्रश्न रखा कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसके अपने नाम से होती है।

वस्तुत: भारत केवल एक भौगोलिक सीमा या राजनीतिक व्यवस्था का नाम नहीं है। यह एक प्राचीन सभ्यता, जीवंत संस्कृति और निरंतर प्रवाहित राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। हजारों वर्षों की ज्ञान-परंपरा, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, विज्ञान, लोकजीवन, संघर्ष और आत्मबल ने उसकी पहचान निर्मित की है। यह भी उल्लेखनीय है कि हर भाषा की अपनी प्रकृति, परंपरा और सांस्कृतिक स्मृति होती है। शब्द केवल ध्वनियां नहीं होते; वे इतिहास, भाव, मूल्य, अर्थ और पहचान के वाहक होते हैं। इसी कारण किसी व्यक्ति, स्थान अथवा राष्ट्र की संज्ञा का सामान्यत: अनुवाद नहीं किया जाता। नाम केवल संबोधन नहीं होता, बल्कि अस्तित्व और अस्मिता का प्रतीक होता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम 'काव्य' हो तो उसे 'पोएट्री' और 'सुंदर' हो तो 'हैंडसम' कहकर नहीं पुकारा जाएगा। इसी प्रकार किसी राष्ट्र की भी अपनी मौलिक पहचान उसके वास्तविक नाम से ही होती है। भाषा की इसी संवेदनशीलता की उपेक्षा के कारण अंग्रेज़ीकरण की प्रवृत्ति ने अनेक विकृतियां उत्पन्न की हैं। राम का 'रामा', कृष्ण का 'कृष्णा', शिव का 'शिवा' और तनुज का 'तनुजा' आदि कर देने से केवल उच्चारण नहीं बदलता, बल्कि कई बार शब्द का अर्थ और लिंग भी परिवर्तित हो जाता है। यदि व्यक्तियों के नामों के साथ ऐसा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं हो सकता, तो करोड़ों लोगों की सभ्यतागत पहचान वाले राष्ट्र के नाम के साथ यह असावधानी कैसे स्वीकार की जा सकती है?

'भारत' कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का स्वनाम है। इसकी जड़ें हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा में हैं। ऋग्वैदिक साहित्य, महाभारत, विष्णु पुराण तथा अनेक प्राचीन ग्रंथों में 'भारत' और 'भारतवर्ष' का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध श्लोक - 'उत्तरं यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। वर्षं तद भारतं नाम भारती यत्र सन्तति:' - सहस्राब्दियों से इस भूमि की सांस्कृतिक पहचान का उद्घोष करता आया है। भारतीय परंपरा के अनुसार इस राष्ट्र का नामकरण चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत के नाम पर हुआ। इसके विपरीत 'इंडिया' एक बाह्य नाम है, जिसकी उत्पत्ति सिंधु (इंडस) के विदेशी उच्चारण से हुई और जिसे औपनिवेशिक शासन ने आधिकारिक रूप से स्थापित किया।

विश्व के अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपने मूल नामों और सांस्कृतिक प्रतीकों को पुन: प्रतिष्ठित किया। अधिक दूर क्यों जाएं, हमारे पड़ोस के देश 'सीलोन' ने 'श्रीलंका' और 'बर्मा' ने 'म्यांमार' कहे जाने में गर्व की अनुभूति की। वस्तुत: प्रत्येक स्वाभिमानी राष्ट्र अपने स्वनाम को अपनी सांस्कृतिक पहचान का आधार मानता है। ऐसे में भारत द्वारा अपने वास्तविक नाम 'भारत' को प्रतिष्ठित करने का आग्रह न तो असामान्य है और न ही अभूतपूर्व; यह प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वाभाविक अधिकार है। यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 'भारत' नाम को लेकर गंभीर और सार्थक चर्चा हुई थी। अनेक सदस्यों ने आग्रह किया था कि संविधान में राष्ट्र का मूल नाम 'भारत' ही होना चाहिए। यद्यपि तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों में अनुच्छेद 1 में 'इंडिया दैट इज भारत' का स्वरूप स्वीकार किया गया, तथापि संविधान सभा की बहस यह स्पष्ट करती है कि 'भारत' केवल एक भाषाई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अनेक अवसरों पर कहा है कि 'भारत' एक विशिष्ट संज्ञा है, उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। जैनाचार्य विद्यासागर महाराज भी निरंतर यह प्रश्न उठाते रहे कि जब मद्रास का चेन्नई, कलकत्ता का कोलकाता, बॉम्बे का मुंबई, गुरुगांव का गुरुग्राम हो सकता है, तो 'इंडिया' का 'भारत' क्यों नहीं हो सकता? उनके अनुसार, यह केवल नाम परिवर्तन का नहीं, बल्कि मानसिक दासता से मुक्ति का प्रश्न है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की प्रसिद्ध पंक्तियां - 'भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है; एक देश का नहीं शील यह, भूमंडल भर का है' - यह स्पष्ट करती हैं कि 'भारत' एक भूभाग का नहीं, बल्कि एक जीवन-मूल्य और सभ्यतागत आदर्श का नाम है। क्या यह भाव 'इंडिया' शब्द से व्यक्त हो सकता है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जनमानस की वाणी 'भारत' ही थी।

'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' जैसे उद्घोष राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बने। प्रश्न है- यदि कोई 'इंडिया माता की जय' कहे तो क्या उससे वही भाव प्रकट होगा जो 'भारत माता की जय' से होता है? इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र की आत्मा सदैव 'भारत' नाम से ही स्वयं को अभिव्यक्त करती रही है। हाल के वर्षों में भी राष्ट्रीय जीवन में 'भारत' के प्रयोग की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ी है। जी-20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण-पत्रों में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' का प्रयोग हो अथवा अनेक सरकारी दस्तावेजों और संस्थानों द्वारा 'भारत सरकार' तथा 'भारत' शब्द को प्राथमिकता देना, ये सभी संकेत इस बात के द्योतक हैं कि देश की सांस्कृतिक चेतना अपने वास्तविक नाम की ओर स्वाभाविक रूप से लौट रही है।

शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं होती है। वह राष्ट्रीय चेतना का निर्माण भी करती है। जब किसी विद्यार्थी को मिलने वाली उपाधि, अंकपत्र या प्रमाण-पत्र पर 'भारत' अंकित होगा, तो वह केवल एक शब्द नहीं पढ़ेगा, बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का भी बोध करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालयों द्वारा आरंभ किए गए इस ऐतिहासिक अभियान का अनुसरण अन्य शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी करें। जिस दिन देश के प्रत्येक अंकपत्र, उपाधि, शासकीय दस्तावेज, न्यायिक अभिलेख, सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक व्यवहार में स्वाभाविक रूप से 'भारत' प्रतिष्ठित हो जाएगा, उस दिन यह केवल शब्द का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय आत्मबोध के एक नए अध्याय का उद्घाटन होगा। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत केवल हमारे देश का नाम नहीं है; वह हमारी सभ्यता की स्मृति, संस्कृति की चेतना, इतिहास की निरंतरता और राष्ट्रीय आत्मा का स्वर है। इसलिए 'इंडिया' से 'भारत' की यह यात्रा किसी शब्द-परिवर्तन का अभियान नहीं, बल्कि स्वत्व, स्वाभिमान, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सभ्यतागत पुनर्जागरण की पुनर्प्रतिष्ठा है। जब कोई राष्ट्र स्वयं को अपने वास्तविक नाम से पुकारना प्रारंभ करता है, तभी वह अपनी आत्मा, अपने इतिहास और अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ पूर्णत: एकाकार होता है।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

अभिनेता और कार्यकर्ता डैनी ग्लोवर अल्जाइमर रोग से ग्रस्त

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

न्यूयॉर्क/एपी। 'लीथल वेपन' फिल्म में एक सहज स्वभाव वाले पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता डैनी ग्लोवर ने खुलासा किया कि वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। चार बार एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके ग्लोवर ने 'टुडे' और पीपल पत्रिका को बताया कि तीन वर्ष पहले उनमें इस बीमारी का पता चला था। डैनी, 22 जुलाई को 80 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने पीपल पत्रिका से कहा, मैं अब भी अपने मन से इसके सभी पहलुओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। कई ऐसे पल होते हैं जिन्हें याद करके यह एहसास होता है कि आप अब भी चीजों को याद रख सकते हैं। और कुछ पल ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भुलूंगा।

अमेरिका में 60 लाख से अधिक लोग और दुनिया भर में लाखों अन्य लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं, जो डिमेंशिया का सबसे सामान्य रूप है। ग्लोवर को चार बार एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और वर्ष 2022 में उन्हें मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ग्लोवर ने वर्ष 1998 से 2004 तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना दूत के रूप में भी कार्य किया।

प्रदर्शन

पटियाला में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय के बाहर अपनी नौकरियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान मॉल रोड को जाम करते पीएसपीसीएल आउटसोर्स एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्य ।

पिकअप ट्रक चला रहे 11 साल के लड़के ने थाई भिक्षुओं के समूह को कुचला, 9 लोगों की मौत

बैंकॉक/एपी। थाईलैंड के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक पिकअप ट्रक चला रहे 11 वर्षीय लड़के ने तीर्थयात्रा पर जा रहे भिक्षुओं के समूह को कुचल दिया। इस दुर्घटना में नौ लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुकदहन प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर निकले थे। मुकदहन के गवर्नर वोरयान बूननारत के अनुसार, पांच भिक्षुओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार भिक्षुओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 13 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से तीन भिक्षुओं की हालत गंभीर है। यह समूह दुर्घटना से लगभग 30 मिनट पहले उबोन रत्चाथानी प्रांत तक की 260 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकला था। स्थानीय बचाव समूह रुआम जाई मुकदहन रेस्क्यू एसोसिएशन' द्वारा साझा किए गए फुटेज में भिक्षु सड़क के किनारे एक कतार में चलते दिखाई दे रहे हैं, तभी पिकअप ट्रक उन्हें कुचल देता है।

स्थानीय पुलिस ने बताया कि लड़का फिलहाल हिरासत में है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि, पुलिस के अनुसार, भिक्षुओं ने बताया कि उन्होंने वाहन को सड़क पर अनियंत्रित होकर लहराते हुए देखा था, जिसके बाद वह सड़क से नीचे उतर गया और समूह से जा टकराया।

सनी देओल के साथ काम करना मेरे कैरियर के लिए सौभाग्य की बात : दीया मिर्जा

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने अभिनेता सनी देओल के साथ काम करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिनेता के साथ काम करना, उनके करियर के लिए सौभाग्य की बात है। फिल्म 'इक्का' में दीया मिर्जा और सनी देओल साथ दिखाई देंगे। 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बात करते हुए दीया ने कहा कि वह हमेशा से देओल परिवार की प्रशंसक रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हां कहने की वजह बताते हुए दीया ने कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे यह बहुत दिलचस्प, मानवीय और दमदार लगी। इसमें किरदारों को बहुत अनोखे, दिलचस्प और आकर्षक ढंग से दिखाया गया है, इसलिए मुझे हां कहना ही पड़ा। सनी देओल के साथ काम करना मेरे करियर के लिए सौभाग्य की बात है और मैं इसे लेकर बहुत खुश थी।उन्होंने अपने को-स्टार्स तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना की भी तारीफ की।

दीया मिर्जा ने कहा कि मैं हमेशा से देओल परिवार की दयालुता, उदारता और जमीन से जुड़े रहने की तारीफ करती रही हूं। सनी देओल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था, बल्कि उससे भी बेहतर्। मैंने टीजर लॉन्च के समय भी यह बात कही थी। ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जिसमें तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हों, यह सच में अद्भुत है और सिद्धार्थ ने कहानी को बहुत संवेदनशीलता और समझदारी से पेश किया है।दीया मिर्जा ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि अवंतिका एक ऐसी महिला है जो अपने आसपास के लोगों को अपनापन, हिम्मत और स्थिरता देती है, तब भी जब जिंदगी बहुत अनिश्चित हो जाती है। मैं उसकी हिम्मत और उस शांत साहस से प्रभावित हुई जिसके साथ वह अपनी चुनौतियों का सामना करती है।

उन्होंने कहा कि 'इक्का' की खासियत यह है कि कोर्टरूम ड्रामा के पीछे परिवार, प्यार और मुश्किल फैसलों की एक गहरी मानवीय कहानी है। मैं नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी कहानी के साथ वापसी करके बहुत खुश हूं जो भावनात्मक रूप से समृद्ध और बहुत दिलचस्प है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे जरूर देखेंगे।

भारत, जापान ने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की

नई दिल्ली/दक्षिण भारत । भारत और जापान ने बृहस्पतिवार को आर्थिक साझेदारी ढांचा एवं सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रक्षा समझौते समेत कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष सनाए तकाइची के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद इन कदमों की घोषणा की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें आर्थिक सुरक्षा पर एक घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त वक्तव्य और ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में सहयोग को मजबूत करने के वास्ते एक समझौता शामिल है। दोनों पक्षों ने जहाज निर्माण और विमानन के क्षेत्र में सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया बयान में कहा, आज के अनिश्चितता के दौर में भारत और जापान दोनों ही आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, हमने आज आर्थिक सुरक्षा के लिए एक संयुक्त खाका तैयार किया है। मोदी ने कहा, इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति शृंखला को अधिक सुदृढ़ और लचीला बनाएंगे। मोदी और तकाइची ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया। मोदी ने कहा, आज भारत और जापान दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। एक स्वतंत्र, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र हमारा साझा प्राथमिक लक्ष्य है। इनके माध्यम से हम पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग संयुक्त रूप से प्रशस्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा, भारत-जापान बायोगैस पहल के माध्यम से हम भारत में एक हजार बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करेंगे। इससे भारत के गांवों में समृद्धि आएगी तथा ग्रामीण आजीविका को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, हमने तेल संकट जैसी स्थितियों से निपटने के लिए ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल भी की है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''इसके अलावा बैटरियों, हरित हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग दुनिया के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।'' मोदी ने कहा कि भारत और जापान आर्थिक सुरक्षा को साझा सुरक्षा के रूप में देखते हैं और ऊर्जा परिवर्तन को एक साझा अवसर के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा, ''हम इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।'

अमरनाथ यात्रा

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के नुनवान बेस कैंप में गुरुवार, को वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले एक तीर्थयात्री की मदद करते सुरक्षाकर्मी।

मुंबई में पानी की कमी से परेशान कनिका महेश्वरी, बोलीं- अब हर बूंद का हिसाब रखना पड़ता है

मुंबई/एजेन्सी

टीवी अभिनेत्री कनिका महेश्वरी ने मुंबई में बढ़ते जल संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी एक ऐसी समस्या है, जो लोगों की पूरी दिनचर्या बदल देती है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। कनिका महेश्वरी ने कहा, ''पानी की कमी का असर हर छोटे-बड़े काम को प्रभावित करता है। जब सुबह उठते ही यह चिंता हो कि खाना बनाने, सफाई करने या रोजमर्रा की साफ-सफाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा या नहीं, तब समझ आता है कि पानी जैसी जरूरी चीज कितनी अनमोल है। हम अक्सर शहर के विकास और बेहतर सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन सम्मानजनक जीवन की सबसे पहली जरूरत नियमित और साफ पानी है।'' कनिका ने कहा, लगातार पानी की कमी लोगों को अपनी जीवनशैली बदलने पर मजबूर कर देती है। पहले जहां लोग आराम से शॉवर लेते थे, वहीं अब पानी बचाने के लिए बाल्टी से नहाना पड़ता है। हर लीटर पानी सोच-समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। आप अपनी जरूरतों से ज्यादा पानी की खपत का हिसाब लगाने लगते हैं। यह परेशानी हजारों परिवार हर दिन झेलते हैं।

जब तक कोई खुद इस स्थिति से नहीं गुजरता, तब तक उसके मानसिक बोझ को समझ पाना आसान नहीं होता।

उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि जल प्रबंधन को लंबे समय की योजना के रूप में देखा जाए। शहर लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए पानी की व्यवस्था भी उसी हिसाब से मजबूत होनी चाहिए। लोगों को हर बार पानी की कमी के हिसाब से अपनी जिंदगी ढालने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। साफ और नियमित पानी की आपूर्ति कोई सुविधा नहीं, बल्कि हर परिवार का बुनियादी अधिकार है।

कनिका ने कहा, पानी बचाने की आदत सिर्फ संकट के समय नहीं होनी चाहिए। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी पानी की बर्बादी रोकनी होगी। जहां रिसाव हो, उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। जितना संभव हो, पानी का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए और छोटी-छोटी सावधानियां अपनानी चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो हम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाले कल को सुरक्षित बना सकती है।

शुद्ध हिंदी बनाम ओरी : उर्वशी रौतेला ने कर दिया उन्हें पूरी तरह कनफ्यूज

मुंबई/एजेन्सी

सोशल मीडिया स्टार ओरी और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला एक बार फिर अपने मजेदार रील के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस बार दोनों एक बस स्टॉप पर बैठे नजर आते हैं, तभी वहां से गुजर रहा एक शख्स उनसे पूछता है, आप यहां क्या कर रहे हो? इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी बातचीत, जो देखते ही देखते बेहद हास्यास्पद मोड़ ले लेती है। जैसे ही ओरी, उर्वशी के साथ अपनी दोस्ती का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, वह सही शब्द तलाशने में उलझ जाते हैं और अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। तभी उर्वशी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आती हैं और शुद्ध हिंदी में अपनी दोस्ती की विस्तृत व्याख्या करती हैं। उनकी भाषा और अंदाज सभी को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन ओरी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उर्वशी की शुद्ध हिंदी सुनकर ओरी के चेहरे पर उलझन साफ नजर आती है। वह चुपचाप यह समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। दोनों की शानदार केमिस्ट्री, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और हल्के-फुल्के हास्य से भरपूर यह रील मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।

जो मेरी पोस्ट पसंद करते हैं, वही सबसे ज्यादा खुश, समझदार और खूबसूरत हैं : काजोल

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल अपनी शानदार अदाकारी के साथ-साथ अपने चुलबुले अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। वह जब भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती हैं तो उनके फैंस उसे खूब पसंद करते हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी एक नई फोटो पोस्ट की, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा उनके साथ लिखे गए मजेदार कैप्शन की हो रही है। काजोल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक मुस्कुराती हुई सेल्फी पोस्ट की। यह सेल्फी उन्होंने कार के अंदर क्लिक की है। लुक की बात करें तो वह पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही है। इसके साथ उन्होंने डायमंड और रूबी चोकर नेकलेस पहना हुआ है। लाइट मेकअप के साथ उनका लुक काफी आकर्षक लग रहा है। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''मेरी बनाई हुई एक स्टडी के अनुसार, जो लोग मेरे पोस्ट लाइक करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा खुश, ज्यादा इंटेलिजेंट और बेहतर दिखने वाले होते हैं, जो उन्हें लाइक नहीं करते।''

अगर काजोल के अभिनय सफर की बात करें तो उन्होंने साल 1992 में 'बेखुदी' फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों जैसे- 'बाजीगर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'करण अर्जुन', 'गुप्त', 'प्यार तो होना ही था', 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम', 'फना', 'माय नेम इज खान', 'दिलवाले', 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' और 'लस्ट स्टोरीज 2' में काम किया। फैंस उनकी जोड़ी को अभिनेता शाहरुख खान के साथ ज्यादा पसंद करते है। वह मशहूर अभिनेत्री तनुजा और दिवंगत फिल्म निर्माता शोमू मुखर्जी की बेटी हैं। उन्होंने साल 1999 में अभिनेता अजय देवगन से शादी किया। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी न्यासा देवगन और बेटा युग देवगन।

'वेलकम टू द जंगल' की सफलता में आपका आशीर्वाद भी शामिल : अक्षय कुमार

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही दर्शकों और समीक्षकों दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी बीच अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें फिल्म से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों फरीदा जलाल और किरण कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। अक्षय ने कहा कि फिल्म की सफलता में उनका आशीर्वाद और अनुभव शामिल है।

अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह फरीदा जलाल और किरण कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में तीनों मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देते दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ अक्षय ने कैप्शन में अपने दिल की बात साझा की है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ''अगर एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, तो यह तस्वीर मेरे लिए लाखों इमोशन्स के बराबर है। 'बड़ी बी' सही कह रही हैं। इस समय जो मैं महसूस कर रहा हूं, उसके सामने धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है।''

उन्होंने आगे कहा, ''मैं 'वेलकम टू द जंगल' से जुड़े हर एक व्यक्ति का आभारी हूं, लेकिन खास तौर पर मैं फरीदा जी और किरण सर जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने नतमस्तक हूं। शायद इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी फिल्म को दर्शकों का इतना अपार प्यार मिल रहा है। पूरी टीम की तरफ से आप सभी को प्यार्। जय महाकाल।'' फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लोकप्रिय 'वेलकम' फिल्म फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है, जबकि इसका निर्माण फिरोज ए. नाडियाडवाला ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, संजय दत्त, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल और किरण कुमार जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। यह फिल्म 22 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से ही इसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

जयपुर एयरपोर्ट पर उर्वशी रौतेला का 'स्पोर्ट्सी' अंदाज : पुर्तगाल की जर्सी में आईं नजर, रोनाल्डो के लिए दिखी दीवानगी

जयपुर/एजेन्सी

बॉलीवुड की ग्लैमरस अभिनेत्री उर्वशी रौतेला मंगलवार को जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचीं, तो वहां मौजूद यात्री और फैंस उनका अंदाज देखकर हैरान रह गए। शहर के प्रतिष्ठित रामबाग पैलेस में आयोजित एक शाही शादी समारोह में शिरकत करने के बाद उर्वशी मुंबई के लिए रवाना हो रही थीं। अमूमन अपने हाई-फैशन और ट्रेडिशनल लुक्स के लिए जानी जाने वाली उर्वशी इस बार पूरी तरह से स्पोर्ट्स मोड में नजर आईं। उर्वशी एयरपोर्ट पर पुर्तगाल फुटबॉल टीम की जर्सी पहनकर पहुंचीं, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों और पैपराजी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। एयरपोर्ट पर उर्वशी ने मुस्कुराते हुए मीडिया और फैंस के सामने अपनी जर्सी की ओर इशारा किया और बताया कि वे पुर्तगाल की फुटबॉल टीम को दिल से सपोर्ट करती हैं। दरअसल, फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रति उर्वशी की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। वे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों और सोशल मीडिया पर रोनाल्डो के लिए अपना फैंस बॉय/गर्ल मोमेंट जाहिर कर चुकी हैं। इसी दीवानगी की झलक आज जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली।

उर्वशी को एयरपोर्ट पर देखते ही उनके प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। कई फैंस उनके साथ सेल्फी और क्लोज-अप फोटो लेने के लिए सुरक्षा घेरे (ड्शर्लीीळू ड्रूशी) को पार करते हुए सीधे डिपार्चर गेट तक पहुंच गए। लगातार बढ़ती भीड़ और अफरा-तफरी के माहौल को देखते हुए सीआईएसएफ (उखडऋ) और एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मियों को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा।सुरक्षा अधिकारियों ने प्रशंसकों को पीछे हटाते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। हालांकि, उर्वशी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया; डिपार्चर गेट के अंदर एंट्री लेने से ठीक पहले उन्होंने रुककर मुस्कुराते हुए फैंस के साथ तस्वीरें क्लिक करवाईं और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया।

जयपुर प्रवास के बारे में बात करते हुए उर्वशी ने राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और यहां के शाही आतिथ्य की जमकर तारीफ की। गौरतलब है कि उर्वशी इससे पहले भी कई बार जयपुर आ चुकी हैं और हर बार वे यहां के ट्रेडिशनल अंदाज की मुरीद हो जाती हैं।

फ़ैशन, लग्ज़री और सदाबहार स्टाइल लेकर आ रही हाई लाइफ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। फैशन और स्टाइल के लिए मशहूर हाई लाइफ प्रदर्शनी का बेंगलूरु में आगाज होने जा रहा है। यह 3 जुलाई को द ललित अशोक में शुरू होगी। प्रदर्शनी 5 जुलाई तक जारी रहेगी। आयोजकों ने बताया कि हाई लाइफ इस सीज़न के सबसे पसंदीदा डिज़ाइनर कलेक्शन की शानदार प्रदर्शनी के साथ वापस आ रही है। यहां देश के जाने-माने डिज़ाइनर्स के शानदार ऑकेज़न वियर, मॉडर्न फ़ैशन, हाथ से बनी ज्वेलरी, लग्ज़री एक्सेसरीज़, होम डेकोर और लाइफ़स्टाइल ब्रांड्स उपलब्ध रहेंगे।उन्होंने कहा कि चाहे आप किसी खास मौके के लिए खरीदारी कर रहे हों या अपने वॉर्डरोब को नया रूप दे रहे हों, यहां आकर फ़ैशन, लग्ज़री और सदाबहार स्टाइल की दुनिया का आनंद ले सकते हैं। फैशनप्रेमियों को हाई लाइफ प्रदर्शनी का बेसब्री से इंतजार रहता है।

तेयुप आआर नगर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में तेरापंथ युवक परिषद द्वारा संचालित आचार्य तुलसी डाइग्नोस्टिक सेंटर आरआर नगर एवं केंगेरी में अध्यक्ष सरल पटावरी के अध्यक्षता में संयोजक पंकज बैद एवं अन्य डाक्टरों व चिकित्सीय टीम की बैठक हुई जिसमें एटीडीसी सेन्टर में कार्यरत डॉक्टर्स, टेक्नीशियन टीम का सम्मान किया गया। इस मौके पर एटीडीसी टीम से संजय बैद, राजेश भंसाली, गुलाब बाँठिया आदि अनेक सदस्य उपस्थित थे।

सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हुब्बल्ली आगमन पर पहुंचे जी. परमेश्वर का हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा समन किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य एफएच जकपानवार, कांग्रेस नेता महेन्द्र सिंघी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ हलूर, अभय सूजी सहित अन्यों ने उपमुख्यमंत्री का सम्मान किया।

दपरे ने 'नेशनल डॉक्टर्स डे' मनाया और सीपीआर ट्रेनिंग आयोजित की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बल्ली। दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) के मेडिकल विभाग ने डॉक्टरों की समर्पित सेवाओं को सम्मान देने और हेल्थकेयर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से कई कार्यक्रमों के साथ 'नेशनल डॉक्टर्स डे' मनाया। हुब्बल्ली के सेंट्रल हॉस्पिटल में, दपरे की प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर डॉ. शोभा जैस्मीन एस. ने डॉक्टरों से बातचीत की और रेलवे हेल्थकेयर में उनकी समर्पित सेवा की सराहना की। सीनियर डॉक्टरों को सम्मानित किया गया और उनसे 'फिजिशियन शपथ' (डॉक्टर की शपथ) भी दिलाई गई, जिसमें उन्होंने नैतिक और संवेदनशील मेडिकल प्रैक्टिस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों ने भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और डॉक्टरों को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर, बेंगलूरु के डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल ने लगभग 50 हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए हेल्थ चेक-अप और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और एचआईवी की स्क्रीनिंग शामिल थी। सुब्रह्मण्य रोड स्टेशन पर हेल्थ यूनिट/कबाकापुत्तुर द्वारा एक जनरल हेल्थ कैंप भी लगाया गया, जहाँ हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मोटापे की स्क्रीनिंग की गई और छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज किया गया।

मेडिकल विभाग ने कैरिज वर्कशॉप, हुब्बल्ली के अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर)ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया। इस प्रोग्राम में बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और सीपीआरका लाइव डेमो दिखाया गया, जिसमें जीवन बचाने वाली ज़रूरी तकनीकें और इमरजेंसी में की जाने वाली कार्रवाई के तरीके शामिल थे। अधिकारियों, सुपरवाइजरों और स्टाफ ने इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

सामाजिक विकास के लिए सही हाथों में हो समाज की बागडोर : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सादनगर। गुरुवार को सादनगर स्थित एक फार्म हाउस में हैदराबाद की विभिन्न धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि सामाजिक विकास के लिए योगदान तथा उसकी कार्ययोजनाओं और व्यवस्थाओं के संदर्भ में हम सबको पारसी, गुजराती व कच्छी समाज से सीखने की आवश्यकता है। इन समाजों ने डेढ़ सौ-दो सौ वर्ष पहले ही सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में ठोस कार्ययोजनाओं को साकार कर लिया था।

अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए सांस्कृतिक भवन, मातृभाषा की शिक्षा, शैक्षणिक सहायता, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, चिकित्सा के लिए सहयोग और छोटे-बड़े अस्पतालों के निर्माण, सामान्य वर्ग के लिए शहरों में होस्टल व सेनिटोरियम, सामूहिक विवाह, कुप्रथाओं के उन्मूलन हेतु चिंतन-मंथन, सामान्य वर्ग के जीवनयापन के लिए जरूरी सभी सुविधाएं, गृहउद्योग द्वारा रोजगार, विधवाओं को आर्थिक सहायता आदि अनेक-अनेक कार्य सुचारू रूप से दशकों पहले से संचालित हो रहे हैं। सामाजिक उत्कर्ष की इतनी सारी योजनाओं के क्रियान्वयन को देखकर हर कोई गौरव की अनुभूति कर सकता है। धन, ज्ञान और सामर्थ्य का यह सही उपयोग है।

आचार्यश्री ने कहा कि समाज की बागडोर सही हाथों में होनी चाहिए। अयोग्य अथवा अपरिपक्व लोगों के पास सत्ता आने से समाज का भारी नुकसान होता है। ट्रस्ट मंडल या समिति में दो-चार गलत लोगों के आ जाने से भी समाज के कार्य रुक जाते हैं और समय के साथ चलती सामाजिक विकास की धारा टूट जाती है।

हर व्यक्ति को सत्ता नहीं, समर्पण और सेवा की भावना से ही किसी भी धार्मिक-सामाजिक संस्था में पदाधिकारी बनना चाहिए। गणि पद्मविमलसागरजी ने कहा कि समाज को अपने घर की तरह समझना होता है, तभी समाजहित के कार्य किए जा सकते हैं। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो उसके लिए सर्वस्व लगा देते है। भिन्न भिन्न समाजों और विविध क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने अपने विचार व अनुभव प्रस्तुत किए। सबने सामाजिक विकास के संकल्प को दोहराया।

धर्म का वास्तविक स्वरूप मानवता की सेवा है : कथा वाचक राजनंदिनी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का चौथे दिवस के मौके पर क्षेत्र के विधायक एवं कर्नाटक सरकार के पूर्व शहरी विकास मंत्री बीए बैरती बसवराज, पार्षद जयप्रकाश ने भी कथा श्रवण की तथा राजपूताना सेवा संगठन द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कथा वाचिका राजनंदिनीजी ने श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराते हुए कहा कि भागवत कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य माध्यम है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, सेवा, सत्य, धर्म और कर्तव्य का अनुपम संदेश देता है। जिस परिवार और समाज में भगवान के नाम का स्मरण, सत्संग और भागवत कथा का श्रवण होता है, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी वास होता है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से अपने जीवन में सदाचार, संस्कार, सेवा, परोपकार एवं राष्ट्रहित की भावना को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि धर्म का वास्तविक स्वरूप मानवता की सेवा और सभी के प्रति प्रेमभाव रखना है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति-रस में इतने भाव-विभोर हुए कि पूरा पंडाल भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया गया।

प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तिभाव से मनाया गया परमात्मा का जन्म कल्याणक महोत्सव

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। स्थानीय शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट, सोलस-2 में गच्छाधिपति जैनाचार्य युगभूषणसूरीश्वरजी (पंडित महाराज), आचार्यश्री अरिहंत सागरजी एवं अनेक साधु साध्वियों की निश्रा में अंजनशलाका महोत्सव के तहत गुरुवार को परमात्मा का जन्म कल्याणक, नामकरण संस्कार, पाठशाला गमन के प्रसंगों को भावपूर्ण तरीके से जीवंत किया गया। प्रातः काल से ही जिनालय परिसर में उत्सव का माहौल था। प्रभु के जन्म कल्याणक के प्रसंग पर पूरा पंडाल 'जय जिनेंद्र' और 'वामा नंदन वीर की' के जयकारों से गूंज उठा। प्रियंवदा बनी दीप्ती द्वारा परमात्मा के जन्म का समाचार अश्वसेन महाराजा को देना, इसके बाद परमात्मा का पालना झूलाने की रस्म और नामकरण संस्कार आनंदोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर बालपन की क्रियाओं के तहत प्रभु का पाठशाला गमन, विवाह, मायरा, राज्याभिषेक, नव लोकान्तिक देवों द्वारा दीक्षा के निवेदन का दृश्य भी दर्शाया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। आचार्यों ने अपने मांगलिक प्रवचन में सभी कल्याणकों के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और श्रावक-श्राविकाओं को संयम व भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस मौके पर ट्रस्ट के ट्रस्टी किशोर जैन, अशोक नागौरी, कुशलराज गुलेच्छा, प्रतिष्ठा महोत्सव के संयोजक अरविन्द कोठारी सहित तेजराज गुलेच्छा, विनोद पोकरना, महेश नाहर, रमेश बोहरा, मोहन नागौरी, विजय मेहता, रचित जैन, महेन्द्र कुमार रांका, राजू सुजानी, नेमीचंद रांका आदि अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

तेयुप विजयनगर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के तेरापंथ युवक परिषद विजयनगर के सदस्यों ने डाक्टर दिवस के मौके पर उनके द्वारा संचालित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेन्टर में कार्यरत डाक्टरों व चिकित्सीय टीम का सम्मान किया तथा टीम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

दुख का कारण परिस्थितियाँ नहीं, हमारा अपना अज्ञान है : डॉ. समकित मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित प्रवचन सभा में डॉ. समकित मुनिजी ने मानव जीवन में आने वाले दुखों के वास्तविक कारण और अज्ञान के अंधकार पर प्रवचन दिया। संतश्री ने कहा कि आज का मनुष्य दिन-रात दुखी है, लेकिन वह अपने दुख का कारण बाहर की दुनिया में खोज रहा है। वास्तव में दुख का कारण न कोई व्यक्ति है, न कोई परिस्थिति, बल्कि व्यक्ति का अपना अज्ञान है। मनुष्य केवल अपनी अज्ञानता के कारण ही दुखी होता है। जिसे सत्य का बोध हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह फिर कभी वास्तव में दुखी नहीं होता। संतश्री ने कहा, संसार में हैं तो तकलीफ़ें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी और संकट भी आएँगे।

लेकिन इनका आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वे हमें दुखी कर सकते हैं। बाहर की कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें दुखी करने की शक्ति नहीं रखती। हमारी तकलीफ़ें हमें दुखी नहीं करतीं, बल्कि उन तकलीफ़ों के प्रति हमारा अज्ञान और हमारा दृष्टिकोण हमें दुखी करता है।

प्रवचन का सार प्रस्तुत करते हुए संतश्री ने कहा कि यदि जीवन में स्थायी सुख, शांति और आनंद प्राप्त करना है तो बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने के बजाय अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना अधिक आवश्यक है। आत्मज्ञान ही समता, संतोष और वास्तविक सुख का आधार है। प्रवचन के उपरांत जयनगर संघ की ओर से संतश्री के चरणों में भावपूर्ण कृतज्ञता एवं मंगलकामनाएँ अर्पित की गईं। इस अवसर पर चातुर्मास स्वागत समिति ने घोषणा की कि इस वर्ष के ऐतिहासिक चातुर्मास का स्वागत सामूहिक तेले' की तपस्या के माध्यम से किया जाएगा। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष दीपचन्द भंसाली, मंत्री पदमचंद बोहरा ने सभी का आभार ज्ञापित किया।

तेयुप राजाजीनगर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

डाक्टर दिवस के मौके पर तेरापंथ युवक परिषद, राजाजीनगर द्वारा संचालित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर, डेंटल केयर एवं डे केयर, श्रीरामपुरम में चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे 13 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। तेयुप के अध्यक्ष राजेश देरासरिया, संस्थापक अध्यक्ष सुनील बाफना एव पूर्व अध्यक्ष सतीश पोरवाड़ ने डाक्टरों को शुभकामनाएं दी तथा उनकी सेवाओं को सराहा।

अग्रवाल महिला मंडल की कार्यकारिणी समिति को दी विदाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय अग्रवाल महिला मंडल द्वारा बुधवार को अग्रवाल महिला मंडल की कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल पूर्ण होने के मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज, युवा संघ, महिला मंडल के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष नीरू तायल, सचिव सुनीति अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कविता तायल को समाज के अध्यक्ष सुभाष बंसल, सचिव सतीश गोयल, कोषाध्यक्ष अंकित मोदी, पूर्व अध्यक्ष रतनलाल सिंघल एवं अंजू अग्रवाल ने बधाई दी तथा उनके कार्यकाल की सराहना की। इस मौके पर रंगारंग प्रस्तुतियों, मनोरंजक गतिविधियों, सम्मान समारोह आयोजित किए गए।

बेंगलूरु पुलिस नियमों के पालन की जांच के लिए सभी डे केयर केंद्रों का निरीक्षण करेगी

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु में एक आईटी कंपनी परिसर के अंदर मौजूद डे केयर' केंद्र में छोटे बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद, बेंगलूरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को भरोसा दिलाया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाएगी कि अन्य 'डे-केयर' केंद्र तय नियमों और कानूनों का पालन करते हुए संचालित हो रहे हैं या नहीं।

बेंगलूरु के ब्रुकफील्ड में आईटी कंपनी कैपजेमिनी' के अंदर मौजूद डे-केयर' की पांच महिला कर्मचारियों के खिलाफ छोटे बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एहतियात के तौर पर वह बेंगलूरु में परिसर के भीतर डे केयर सुविधा को कुछ समय के लिए बंद कर रही है। यह घटना उस समय सामने आई जब व्हाट्सऐप के जरिए साझा किए गए वीडियो में बच्चों से कथित दुर्व्यवहार होते देखा गया और इसकी सूचना 'चाइल्ड हेल्पलाइन' को दी गई।

पुलिस आयुक्त सिंह ने कहा, हम शिकायत और सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो की जांच कर रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त और व्हाइटफ़ील्ड के प्रभारी पुलिस उपायुक्त अभी मौके पर मौजूद हैं और तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। इस घटना को बहुत ''गंभीर मामला'' बताते हुए अधिकारी ने कहा कि वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सिंह ने कहा, ''हमें इस घटना के बारे में पहले पता नहीं था।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**